शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 12 | अंक : 348 | गुवाहाटी | शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

सिक्किम सुरंग त्रासदी के बाद चार दिन चला खोज एवं बचाव अभियान... पेज 2
11 जिलों की 653164 आबादी प्रभावित, मृतकों की संख्या 44 हुई पेज 3
विपक्ष में बैठने से देश को गुमराह करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता : शेखावत पेज 5
फीफा विश्व कप-2026 की ड्रीम इलेवन घोषित, मेसी, एम्बाप्पे और हॉलैंड ... पेज 7

अमित शाह ने असम के बाढ़ के हालात की समीक्षा की, 80 से अधिक लापता

25 जिले, 1800 से अधिक गांवों में नौ लाख लोग प्रभावित

गुवाहाटी (हि.स.)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा से बातचीत कर असम की बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। राज्य में बाढ़ से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बातचीत के दौरान अमित शाह ने राज्य को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल आज या कल असम पहुंचेगा। इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा लगातार दूसरे दिन भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर रहे। उन्होंने गोलाघाट जिले में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और नुमलीगढ़ तथा गोलाघाट के कमारबंधा स्थित भास्कर सीनियर बेसिक स्कूल के राहत शिविरों का दौरा कर प्रभावित लोगों से मुलाकात की तथा राहत कार्यों की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि ऊपरी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाओं के कारण अचानक आई बाढ़ ने लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने संकट की इस घड़ी में असम के लोगों के साथ खड़े रहने और केंद्र से सहयोग मिलने के लिए अमित शाह का आभार जताया। सीएम शर्मा के अनुसार, इस बार की बाढ़ के पीछे ऊपरी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं के साथ स्थानीय स्तर पर हुई असाधारण बारिश प्रमुख कारण रही है। राज्य में स्थानीय बारिश सामान्य से 436 फीसदी अधिक दर्ज की गई है। इसके चलते कई ऐसे गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए, जहां हाल के वर्षों में इस स्तर की बाढ़ नहीं देखी गई थी। मुख्यमंत्री ने स्थिति को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि विनाश का पैमाना *अकल्पनीय* है। बाढ़ की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य के 25 जिलों में 1800 से अधिक गांव प्रभावित हैं और नौ लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में आए हैं। बाढ़ ने लोगों के घरों के साथ-साथ खेती, पशुधन और आजीविका को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। हजारों मवेशियों के बह जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ा है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 148 से अधिक राहत शिविर स्थापित किए हैं। इन शिविरों में करीब 30 हजार विस्थापित लोग शरण लिए हुए हैं। प्रभावित परिवारों तक भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने के लिए राहत दल लगातार काम कर रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में अब तक तीन लाख किलोग्राम से अधिक चावल और अन्य आवश्यक राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। अधिकारियों के अनुसार, राहत सामग्री की अतिरिक्त खेप भी लगातार प्रभावित इलाकों में भेजी जा रही है। राज्य सरकार ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए व्यापक राहत और बचाव अभियान शुरू किया है। भारतीय वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), जिला प्रशासन और अन्य राज्य एजेंसियों के जवान प्रभावित क्षेत्रों में चौबीसों घंटे राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर और नावों का इस्तेमाल किया जा -शेष पृष्ठ दो पर

सरकार ने विलय से पहले विधायकों को स्कूल में दाखिले को बढ़ावा देने के लिए एक साल का समय दिया

गुवाहाटी। असम सरकार ने विधायकों को 30 से कम छात्रों वाले स्कूलों में छात्र नामांकन बढ़ाने के लिए एक वर्ष का समय देने पर सहमति जताई है, इससे पहले कि आगे स्कूल विलय की प्रक्रिया शुरू की जाए। शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने गुरुवार को असम विधानसभा को यह जानकारी दी। सरकारी स्कूलों को बंद करने और उनके विलय को लेकर विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए, पेगु ने कहा कि सरकार कम नामांकन वाले स्कूलों को बचाने का अवसर प्रदान करने के लिए तैयार है, बशर्ते निर्धारित अवधि के भीतर नामांकन में सुधार हो। पेगु ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां सत्ताधारी दल, विपक्ष और सभी हितधारकों को मिलकर काम करना चाहिए। बहस कानून की वैधता के बारे में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे सर्वोत्तम तरीके से लागू करने के बारे में होनी चाहिए। सरकार की स्कूल युक्तिकरण नीति का बचाव करते हुए मंत्री ने कहा कि 30 से कम छात्रों वाले स्कूलों के विलय का प्रावधान पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पारित कानून पर आधारित था। उन्होंने कहा -शेष पृष्ठ दो पर

मैदानी जनजातियों के लिए छठी अनुसूची का प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है : पेगू

गुवाहाटी। असम सरकार ने गुरुवार, 23 जुलाई को कहा कि वह कई मैदानी आदिवासी समुदायों की स्वायत्त परिषदों को संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत लाने या राज्य के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के लिए कोई समयसीमा निर्दिष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि दोनों मामले केंद्र सरकार और संसदीय प्रक्रिया के अधीन हैं। असम विधानसभा के 16वें बजट सत्र के 10वें दिन शिवसागर विधायक अखिल गोगोई द्वारा उठाए गए तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए, जनजातीय मामलों (मैदानी) के मंत्री रानोज पेगु ने सदन को सूचित किया कि राभा, तिवा, मिसिंग, देओरी, सोनोवाल कचारी और थेंगल कचारी समुदायों की स्वायत्त परिषदों को छठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव वर्तमान में केंद्र सरकार के विचाराधीन -शेष पृष्ठ दो पर

door graph
Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है।

- आचार्य चाणक्य

नुमलीगढ़ के बाढ़ राहत शिविर पहुंचे मुख्यमंत्री शर्मा, राहत कार्यों का लिया जायजा

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को बोकाखात के नुमलीगढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थापित बाढ़ राहत शिविर का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने शिविर में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने भोजन, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया और जिला प्रशासन व संबंधित विभागों को प्रभावित लोगों की सभी जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री अजंता नेउग और अतुल बोरा भी मौजूद रहे। इस राहत शिविर में वर्तमान में कुल 182 लोग रह रहे हैं, जिनमें 75 पुरुष, 107 महिलाएं तथा 22 किशोर-किशोरियां शामिल हैं। शिविर में विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले चार शिशु, चार स्तनपान कराने वाली माताएं, तीन गर्भवती महिलाएं और एक दिव्यांग व्यक्ति भी हैं। आपातकालीन -शेष पृष्ठ दो पर

पेपर लीक के सभी मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई : प्रधानमत्री

नई दिल्ली। छात्रों द्वारा नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच युवाओं और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स लिखा कि पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा -शेष पृष्ठ दो पर

विपक्ष ने जताया विरोध, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

नई दिल्ली (हि.स.)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के एलान की आलोचना की। -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

सीजेपी ने आज देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध का किया आह्वान

नई दिल्ली (हि.स.)। सोशल मीडिया अभियान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सभी से शुक्रवार को देश के हर जिले में एक दिन के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। इसका मुख्य उद्देश्य *हर जिला, एक दिन, एक मांग* के संदेश के तहत पूरे देश में एकजुटता प्रदर्शित करना है। -शेष पृष्ठ दो पर

छात्रों के समर्थन में उतरे अन्ना, किया दो घंटे का मौन आंदोलन

मुंबई। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गुरुवार को प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में दो घंटे का मौन आंदोलन किया। उनका ये आंदोलन सुबह 11 बजे शुरू हुआ था, जो दोपहर 1 बजे खत्म हो गया। हजारे ने अहिल्यानगर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद वो इसी जिले में स्थित अपने गांव रालेगण सिद्धि के लिए रवाना हो गए। उन्होंने बीते बुधवार को पीएम मोदी -शेष पृष्ठ दो पर

सरकार वार्ता को तैयार, आंदोलनकारी छात्र आवास या कार्यालय आएं : नड्डा

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को कहा कि जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों से सरकार बातचीत के लिए तैयार है। इसके लिए छात्रों को उनके आवास या फिर कार्यालय आना होगा। संसद परिसर में जेपी नड्डा ने कहा किहां, हम तैयार हैं। हमारे घर या हमारे आधिकारिक कार्यालय आ जाइए। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो दोषी हैं उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर कड़ी सजा दी जाएगी। हमारा कांग्रेस और -शेष पृष्ठ दो पर

नीट मामले पर चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ठप

नई दिल्ली। गुरुवार को मॉनसून सत्र के चौथे दिन, संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर *लीक* मामले पर चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग फिर से मुख्य मुद्दा बनी रही। विपक्ष के लगातार विरोध के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी और लगातार चौथे दिन बिना किसी कामकाज के सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दिए गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने और *पहले से शर्तें* थोपने का आरोप लगाया। नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने विपक्ष पर नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में चर्चा के लिए पूर्व शर्त लगाकर इससे भागने का आरोप लगाते हुए -शेष पृष्ठ दो पर

असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा पेश

गुवाहाटी (हि.स.)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा गुरुवार को असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश हुए। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि एवं कथित फर्जी पासपोर्ट मामले में जारी समन के आधार पर वह पूछताछ के लिए गुवाहाटी पहुंचे। यह मामला चुनाव से पहले पवन खेड़ा द्वारा एक प्रेस कांफ्रेंस में रिनिकी भुइयां शर्मा पर कई पासपोर्ट रखने और विदेश में संपत्ति होने का आरोप लगाने से जुड़ा है। आरोपों को खारिज करते हुए रिनिकी भुइयां शर्मा ने उनके खिलाफ जालसाजी, -शेष पृष्ठ दो पर

भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा-

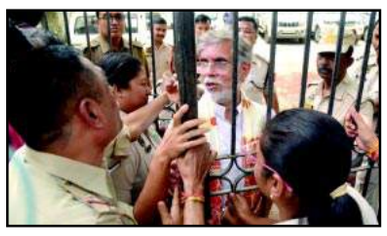

कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा

संयुक्त राष्ट्र (हि.स.)। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि का निलंबित किए जाने को न्यायोचित ठहराया है और कहा है कि पाकिस्तान ने दशकों तक भारत के खिलाफ आतंकवाद को राज्य की नीति में पोषित कर सिंधु जल संधि की बुनियादी भावना को ही खत्म कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में आयोजित *प्राकृतिक संसाधनों का शासन: शांति, सुरक्षा एवं समृद्धि की बुनियाद* विषय पर उच्च स्तरीय खुली बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान पर सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए सिंधु जल संधि पर देश का सख्त रुख दोहराया। हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग करते हुए *झूठी कहानी* पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीमा-पार आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में अपनाने वाले देश के साथ आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित सहयोग संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि को पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को लगातार समर्थन देने से -शेष पृष्ठ दो पर

सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी के घर पर इंडी गठबंधन की बैठक, कई विपक्षी नेता मौजूद

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नई दिल्ली स्थित आवास पर आज गुरुवार को इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई गई। नीट पेपर लीक मामले को लेकर इंडी गठबंधन के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इस बैठक में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी के घर चल रही बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश समेत विपक्ष के कई बड़े नेता पहुंचे हैं। नीट पेपर लीक पर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते संसद का मानसून सत्र बाधित हो रहा है। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार सुबह पेपर लीक मामले में त्वरित सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने की घोषणा की। इसके साथ ही सरकार संसद में नीट पेपर लीक पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार, 22 जुलाई को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि विपक्ष जितना चाहे उतने समय तक सरकार -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
94350-14771

सिक्किम सुरंग त्रासदी के बाद चार दिन चला खोज एवं बचाव अभियान समाप्त, सभी 25 शव बरामद

नाम्ची (हि.स.)। नाम्ची जिले के झोलुंगे अंतर्गत समरदुंग में निर्माणाधीन नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) की तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत परियोजना की सुरंग में पिछले चार दिनों से चलाया जा रहा खोज एवं बचाव अभियान गुरुवार को समाप्त हो गया। सुरंग से सभी 25 पीड़ितों के शव बरामद कर लिए गए हैं। नाम्ची जिला प्रशासन के अनुसार आज के बचाव अभियान के दौरान तीन और शव बरामद किए गए। इसके साथ ही इस हादसे में मृतकों की कुल संख्या 25 हो गई। इसके बाद बचाव दल ने सुरंग का विस्तृत निरीक्षण किया और लापता सभी श्रमिकों के विवरण का मिलान करने के बाद पुष्टि की कि अब सुरंग के भीतर कोई भी व्यक्ति फंसा नहीं है। मृतकों में एनएचपीसी लिमिटेड, एआरएक्स और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के कर्मचारी एवं अधिकारी शामिल हैं। वे भारत के 10 राज्यों के निवासी थे, जिनमें पश्चिम बंगाल के 11, झारखंड के 4, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के 2-2 तथा केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पंजाब और असम के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। बरामद सभी शवों को आवश्यक कानूनी और चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी करने के लिए सिंगताम जिला अस्पताल, एसटीएनएम अस्पताल (गंगटोक), नाम्ची जिला अस्पताल और सेंट्रल रेफरल अस्पताल, मणिपाल भेजा गया है। जिन शवों की पहचान हो चुकी है, उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। खोज एवं बचाव अभियान खत्म होने के बाद जिला प्रशासन ने चार दिनों तक चले इस चुनौतीपूर्ण अभियान में अथक समर्पण, पेशेवर दक्षता और उत्कृष्ट समन्वय के साथ योगदान देने वाले सभी बचाव एजेंसियों और कर्मियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस बीच, राज्य सरकार ने इस दुखद घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है। बचाव अभियान नाम्ची जिला प्रशासन के नेतृत्व में एनएचपीसी के अधिकारियों, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, आसनसोल की माइंस रेस्क्यू टीम, सिक्किम पुलिस, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के घनिष्ठ समन्वय से चलाया गया। अभियान की निरंतर निगरानी सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसएसडीएमए) ने की। दक्षिण सिक्किम के नाम्ची जिले के समरदुंग, झोलुंगे स्थित एनएचपीसी तीस्ता स्टेज-6 जलविद्युत परियोजना की सुरंग में यह हादसा 20 जुलाई की दोपहर हुआ था।

सीजेपी प्रदर्शन में शामिल दंगाइयों का पासपोर्ट होगा रद : पुलिस

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस उन व्यक्तियों के पासपोर्ट रद करने पर विचार कर रही है जो कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में सीधे शामिल पाए गए हैं। यह कड़ी कार्रवाई बुधवार रात जंतर मंतर के पास नीट पेपर लीक मुद्दे पर हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद सामने आई है। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। बता दें कि जंतर मंतर के पास ड्यूटी पर जा रहे इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह ने बताया कि करीब 4,000 से 5,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। वे पुलिस और सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। उन्होंने मुझे लाठियों, डंडों, पत्थरों और जो भी नुकीली चीजें उनके पास थीं, उनसे हमला कर दिया। मैं घायल हो गया और किसी तरह भाग निकला। मैं वर्दी में था, फिर भी उन्होंने मुझ पर हमला किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने उन लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दावा किया गया है। दरअसल, नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ सीजेपी का प्रदर्शन कई दिनों से जंतर मंतर पर जारी है। ज्यादातर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन कुछ हिंसक घटनाओं ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त रुख अपनाने पर मजबूर किया है। पासपोर्ट रद करना दंगे और सुरक्षा बलों पर हमला करने वालों के लिए एक निवारक कदम के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल, दोषियों की पहचान और औपचारिक कार्रवाई को लेकर और जानकारी का इंतजार है।

असम में 26 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट

गुवाहाटी (हिंस)। असम में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। बोरझार स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 जुलाई तक राज्य सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान कई स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने तथा आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। उधर नाजिरा के विधायक मयूर बरगोहाई ने बताया कि बाढ़ से क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। अब तक 55 लोग लापता हैं, जबकि 2, 000 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण लगभग 200 पक्की सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं, बिहुबर क्षेत्र में सड़कों पर आठ फुट तक गाद जमा हो गई है, जिससे आवागमन और राहत कार्य प्रभावित हुए हैं। विधायक ने कहा कि प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य जारी रखे हुए है।

सरकार व आंदोलनकारी मिलकर जल्द सौहार्दपूर्ण समाधान निकालें : मायावती

लखनऊ (हिंस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश की राजधानी नई दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन में विपक्षी दलों के नेताओं की भागीदारी को राजनीतिक लाभ लेने की मंशा करार दिया है।उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार व आंदोलनकारी दोनों मिलकर इसका शान्ति व सौहार्दपूर्ण समाधान जितना जल्द निकालें उतना उचित होगा। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस संबंध में गुरुवार को पोस्ट की है। जिसमें उन्होंने कहा कि पेपरलीक सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद के नजदीक जन्तर-मन्तर में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। अपने भविष्य को लेकर उनके द्वारा जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के कारण सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त हंगामा बरपा है।

पूसीरे का कटिहार और मनिहारी के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन

गुवाहाटी (हिंस)। आगामी श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को सुविधा प्रदान करने के लिए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) ने कटिहार मंडल के अधीन कटिहार और मनिहारी के बीच स्पेशल ट्रेन सेवाओं के परिचालन करने का निर्णय लिया है। वार्षिक श्रावणी मेले में आने वाले हजारों भक्तों, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के लिए सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इन स्पेशल ट्रेनों की योजना बनाई गई है। पूसीरे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने गुरुवार को बताया कि स्पेशल ट्रेनों की एक जोड़ी, ट्रेन संख्या 07540/07539 (कटिहार-मनिहारी-कटिहार) श्रावणी मेला स्पेशल, प्रत्येक दिशा से 22-22 फेरों के लिए चलेगी। 25 जुलाई से 23 अगस्त तक ट्रेन संख्या 07540 प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को कटिहार से 19-00 बजे रवाना होकर मनिहारी 19-45 बजे पहुंचेगी। वापसी दिशा में, 26 जुलाई से 24 अगस्त तक ट्रेन संख्या 07539 प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को मनिहारी से 03-30 बजे रवाना होकर कटिहार 04-15 बजे पहुंचेगी। इस सेवा का ठहराव मनसाही और महियारपुर स्टेशनों पर होगा।

अमृतसर में ड्रग्स-हथियार तस्करों पर कार्रवाई, दो गिरफ्तार

चंडीगढ़ (हिंस)। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार एवं नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है।ड्रग्स-हथियार के तस्करी मॉड्यूल के दो गुर्गों के पास से छह आधुनिक पिस्तौल, एक किलो हेरोइन, एक किलो अफीम और 10 हजार रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान जोगा सिंह (45) निवासी गांव डल्ल, तरन तारन और मनप्रीत सिंह (28) निवासी गांव काली, तरन तारन के रूप में हुई है। बरामद की गई पिस्तौलों में दो .30 बोर एक्स-शॉट, दो .30 (चीनी), एक .30 बोर तुर्की जिगाना और एक .30 बोर पीएक्स5 स्टोर्म शामिल हैं। पुलिस टीमों ने उनकी मोटरसाइकिल जिसका उपयोग तस्करी के लिए किया जाता था, भी जब्त कर लिया है।

पृष्ठ एक का शेष

अमित शाह ने असम...

रहा है। दुर्गम क्षेत्रों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभियान जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल राहत और बचाव कार्यों के साथ ही राज्य सरकार विभिन्न विभागों और केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए दीर्घकालिक पैकेज तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य बाढ़ का पानी उतरने के बाद प्रभावित परिवारों को अपनी जिंदगी और आजीविका दोबारा खड़ी करने में सहायता देना है। राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आपात स्थिति नियंत्रित होने के बाद पड़ोसी राज्यों के साथ संरचित बातचीत शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य ऊपरी क्षेत्रों में बादल फटने और इससे जुड़ी अचानक आने वाली बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र विकसित करना है। केंद्र की टीम के दौरे से नुकसान का विस्तृत आकलन और पुनर्वास के लिए केंद्रीय सहायता का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। फिलहाल राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है।

सरकार ने विलय से ...

कि मैंने 30 से कम छात्रों वाले विद्यालयों की सूची विधायकों के साथ साझा की है। कुछ सदस्यों ने नामांकन बढ़ाने के लिए उन्हें एक वर्ष का समय देने का अनुरोध किया है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें नामांकन 30 से ऊपर लाने के लिए काम करने दीजिए। हालांकि, पेगु ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि एक वर्ष की अवधि के बाद भी नामांकन में सुधार नहीं होता है, तो सरकार के पास विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि अगर एक साल बाद भी छात्रों की संख्या नहीं बढ़ती है, तो हम मौजूदा व्यवस्था को जारी नहीं रख सकते। 30 से कम छात्रों वाले स्कूलों को चलाना आर्थिक और प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इससे एकल शिक्षक वाले स्कूलों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का भी समाधान नहीं होता है। पेगु ने आगे कहा कि राज्य लगभग 50 लाख छात्रों की शिक्षा का प्रबंधन करता है, जिसके लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और वित्त में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। जब किसी वेंचर स्कूल का प्रांतीयकरण किया जाता है, तो सरकार को उसे बुनियादी स्तर से उन्नत करना पड़ता है। इसके लिए पर्याप्त सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता होती है। पिछले पांच वर्षों में, हमने लगभग 20,000 अतिरिक्त कक्षाएं बनाई हैं और नागरिक अवसंरचना में लगभग 15 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगले पांच वर्षों में, 500 और स्कूलों के पुनर्विकास का कार्य शुरू किया जाएगा, उन्होंने कहा। पेगु ने विभाग द्वारा किए जा रहे कई सुधारों की भी रूपरेखा प्रस्तुत की, जिनमें दूरस्थ क्षेत्रों के लिए क्लस्टर-आधारित शिक्षक भर्ती शामिल है ताकि बार-बार तबादलों के अनुरोधों को कम किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षक अपने तैनाती स्थल के करीब रहें। उन्होंने कहा कि सरकार फिलहाल नई भर्ती की योजना नहीं बना रही है, बल्कि कर्मचारियों की संख्या में सुधार के लिए मौजूदा स्वीकृत पदों को युक्तिसंगत बनाएगी। राज्य की प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डालते हुए, पेगु ने कहा कि सरकार ने विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की है, जो एक केंद्रीय निगरानी और मूल्यांकन केंद्र है जो सीखने के परिणामों में सुधार के लिए यूडीआईएसई डेटा का विश्लेषण करता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई छात्र लगातार पांच दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है, तो सिस्टम अनुपस्थिति का कारण जानने और बच्चे को स्कूल लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए माता-पिता, शिक्षकों और स्कूल प्रमुख को स्वचालित रूप से एसएमएस अलर्ट भेजता है। मंत्री ने सदन को आगे सूचित किया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों को एक ही विभाग में विलय कर दिया गया है और सरकार शिक्षकों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए एक सामान्य एकीकृत प्रबंधन नियम तैयार कर रही है। लोअर प्राइमरी (एलपी) शिक्षकों की भर्ती के संबंध में पेगु ने कहा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा होने तक यह प्रक्रिया स्थगित रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम उच्च न्यायालय में मामले लड़ रहे हैं। कानूनी मुद्दों के निपटारे के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पेगु ने शिक्षा क्षेत्र के प्रति सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला और कहा कि शिक्षा को राज्य बजट में सबसे बड़े आवंटनों में से एक प्राप्त होता रहता है। अगर सिर्फ शिक्षा विभाग को ही देखें तो उसे राज्य बजट का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। लेकिन अगर पूरे शिक्षा क्षेत्र को शामिल किया जाए तो यह आवंटन 17 प्रतिशत से अधिक हो जाता है। चिकित्सा शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के लिए अलग-अलग मदों में बजट आवंटित किया गया है। अगर इन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो शिक्षा और मानव संसाधन विकास पर सरकार का कुल खर्च राज्य बजट के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, मंत्री ने सदन को बताया।

मैदानी जनजातियों के ...

है। मंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया पूरी तरह से केंद्र सरकार और संसदीय प्रक्रिया से जुड़ी है। इसलिए, राज्य सरकार इसके पूरा होने के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा निर्धारित नहीं कर सकती। 2016 से इन स्वायत्त परिषदों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के संबंध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, पेगु ने कहा कि सरकार ने विधानसभा के उत्तर के साथ संलग्न परिशिष्ट *ए* में वार्षिक आवंटन, प्रशासनिक व्यय और विकासात्मक व्यय पर परिषद-वार विस्तृत जानकारी प्रदान की है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मोरान, मोटोक, ताई अहोम, चुटिया, कोच-राजबोंगशी और चाय बागान जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए भी कोई समयसीमा नहीं बता सकती, क्योंकि यह मामला भी केंद्र सरकार के पास है और इसके लिए संसदीय मंजूरी की आवश्यकता है। मंत्री ने सदन को आगे सूचित किया कि कलिता और नाथ योगी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि असम सरकार ने पत्र ईसीएफ संख्या 232944/34 दिनांक 10 जनवरी, 2024 के माध्यम से मैदानी अनुसूचित जनजातियों की सूची में मोदाही समुदाय को शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को पहले ही भेज दिया है।

नुमलीगढ़ के बाढ़ राहत ...

सहायता के लिए शिविर का हेल्पलाइन नंबर 9101458671 जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने बोकाखात और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुए नुकसान का भी जायजा लिया तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सह-जिला आयुक्त, राजस्व चक्र अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को राहत वितरण और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

पेपर लीक के सभी...

लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य/सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र नीट पेपर लीक मामले को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों के साथ विपक्षी दल भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। इस बीच किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की बात कही है।

विपक्ष ने जताया ...

राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सरकार ने मिलकर के देश के युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। गांधी ने कहा कि सरकार ने न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार के सामने तीन मांगें रखी है, पहला धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं जाए, दूसरा छात्रों से माफी मांगे और तीसरा छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही आआपा के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए इसे छात्रों के आंदोलन को दबाने की *लीपापोती* करार दिया और मांग की कि सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बजाय पेपर लीक के इस पूरे रैकेट और इसमें शामिल बड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सुबह प्रधानमंत्री ने एलान किया है पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो पहले ही बहुत बने थे, पोक्सो के लिए, रेप केस जैसे कई मुद्दो पर बने है लेकिन उनमें सुनवाई तो होती नही है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सारी बाते कही लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बीत क्यों नही की। केजरीवाल ने दुख जताते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ प्रदर्शन में जो व्यवहार किया गया उस पर सरकार चुप क्यो थी, कोई भी कार्रवाई क्यो नही किया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर साल पेपर लीक का मामला सामने आता है लेकिन प्रधानमंत्री ने एक भी ऐसी बात नही की कि अगले साल नीट पेपर लीक नही होगा। विपक्ष ने सरकार से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे और हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

सरकार वार्ता को ...

विपक्ष से अनुरोध है कि इस विषय का राजनीतिकरण ना करें। भागें मत, चर्चा कीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने 20 जुलाई को जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की थी और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद बुधवार को दोबारा बातचीत के लिए आमंत्रित करने पर सीजेपी नेताओं ने कहा था कि वह उनके आवास या कार्यालय पर नहीं जाएंगे बल्कि किसी अन्य स्थान पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके पहले, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि आंदोलनकारी छात्रों से सरकार कहीं भी बातचीत के लिए तैयार है। दूसरी और सीजेपी सूत्रों के मुताबिक वह सरकार से किसी भी तरह की बातचीत उनके ऑफिस या घर पर नहीं करेगी।

नीट मामले पर ...

कहा कि सरकार तत्काल चर्चा को तैयार है और विपक्ष को बिना देरी के चर्चा शुरू करानी चाहिए। आज सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद वह सदस्यों को उनकी बात रखने का अवसर देंगे। सदन में हंगामा थमते न देख बिरला ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक दो बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि हमने कल भी अपील की और आज भी फिर से सदन से अपील कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामले में चर्चा बिना विलंब के शुरू होनी चाहिए। उधर नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के अड़े रहने के कारण राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी बाधित रही और तीन बार के स्थगन के बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखित पाठ से काव्यात्मक पंक्तियां पढ़ना शुरू करते हुए कहा कि विपक्ष देशहित में हर चुनौती का सामना करेगा। उपसभापति हरिवंश ने उन्हें आगे बोलने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को केवल गतिरोध समाप्त करने और नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा शुरू कराने के उद्देश्य से बोलने का अवसर दिया गया था, जिसके लिए सरकार पहले ही सहमति जता चुकी है।

असम पुलिस की क्राइम...

मानहानि और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पवन खेड़ा को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इससे पहले वह स्वास्थ्य कारणों और बेंगलुरु में पार्टी कार्यक्रम का हवाला देकर कई बार जारी समन पर उपस्थित नहीं हुए थे तथा इसकी जानकारी उन्होंने लिखित रूप से क्राइम ब्रांच को दी थी। क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचने से पहले पवन खेड़ा ने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए समन का पालन करने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें असम आना हमेशा अच्छा लगता है।

कश्मीर भारत का ...

अलग करके नहीं देखा जा सकता। राजदूत पर्वतनेनी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा। यह संवैधानिक और कानूनी सच्चाई है जिसे पाकिस्तान जानबूझकर नजरअंदाज करना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर से जुड़ा एकमात्र लंबित मुद्दा पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा है और भारत पर उंगली उठाने के बजाय, पाकिस्तान अपने घर को ठीक करके अपना और अपने लोगों का ज़्यादा भला करेगा। भारत ने 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, के बाद 23 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति (सीसीएस) की बैठक में सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा था कि यह संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और स्थायी रूप से सीमा-पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। भारत सरकार ने नई दिल्ली में साफ किया है कि अपने निवर्तमान रूप में सिंधु जल संधि फिर से काम नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस संधि में रहना भारत के हित में नहीं है। उन्होंने कहा किभारत ने यह संधि नुकसान उठा कर भी सद्भावना और मैत्री की भावना से की थी लेकिन चार दशकों से सीमापार आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में निर्लज्जता से बढ़ा कर पाकिस्तान ने संधि में वर्णित सद्भावना का उल्लंघन किया है। संधि की नींव को ध्वस्त कर दिया गया है। भारत का कहना है कि जहां उसने युद्धों के दौरान भी छह दशकों से अधिक समय तक संधि का सम्मान किया, वहीं पाकिस्तान के निरंतर सीमा पार आतंकवाद (संसद, मुंबई, उरी, पुलवामा और पहलगाम पर हमलों सहित) ने संधि के लिए आवश्यक आपसी विश्वास और पारस्परिकता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। भारत का मानना है कि जिन परिस्थितियों में वर्ष 1960 में यह संधि हुई थी, वे अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। सूत्रों ने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, आतंकवाद का, राज्य की नीति के रूप में प्रयोग खुद ही एक उल्लंघन है। भविष्य में यदि कोई भी समझौता या बातचीत की जाती है, तो वह आज की वास्तविकताओं जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर रिट्रीट, स्थानांतरण जल विज्ञान, बढ़ती मांग, नई तकनीक और सुरक्षा चिंताओं को प्रतिबिंबित करेगी। पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रयासों पर भारत का कहना है कि सिंधु जल संधि में विवाद समाधान की स्पष्ट प्रक्रिया तय है, जिसकी शुरुआत के दो स्तर द्विपक्षीय आधिकारिक स्तर की बातचीत से होती है, उसके बाद तटस्थ विशेषज्ञ और अंत में आवश्यकता होने पर मध्यस्थता न्यायालय का विकल्प आता है। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान ने सीधे मध्यस्थता न्यायालय का रुख अपनाकर संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया। भारत ने दोहराया कि यह न्यायालय *गैर-कानूनी तरीके से गठित* किया गया था और इसका निर्णय भारत के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। भारत का आरोप है कि भारत सरकार ने वर्ष 2023 में पाकिस्तान से बदलती परिस्थितियों - बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा आवश्यकताओं और आधुनिक तकनीक को देखते हुए संधि की समीक्षा और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर बातचीत से लगातार इनकार करता रहा। सूत्रों ने कहा कि यह संधि 1950 के दशक की परिस्थितियों और तकनीक पर आधारित थी, जबकि आज जल संसाधनों की जरूरतें और चुनौतियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। भारत के अनुसार, संधि के निलंबन के दौरान स्थायी सिंधु आयोग की बैठकें नहीं होंगी, नियमित निरीक्षण बंद रहेंगे, हाइड्रोलॉजिकल और परियोजनाओं से जुड़े डेटा का नियमित आदान-प्रदान नहीं होगा। हालांकि, मानवीय आधार पर पाकिस्तान को बाढ़ संबंधी चेतावनियां जारी करना जारी रहेगा। पिछले बाढ़ सीजन में भारत ने स्वेच्छा से 23 बाढ़ चेतावनियां साझा की थीं। इसके अलावा, भारत का कहना है कि वह सिंधु जल के पूर्ण उपयोग के साथ आगे बढ़ रहा है। दो प्रमुख परियोजनाएं, 624 मेगावाट कीरू और 1000 मेगावाट की पाकल दुल पनबिजली संयंत्र, इस साल चालू होने वाली हैं। भारत आने वाले वर्षों में जम्मू और कश्मीर में और 5500 मेगावाट जोड़ने की योजना बना रहा है। प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं में सावलकोट जलविद्युत परियोजना (1,856 मेगावाट), पाकल दुल परियोजना (1,000 मेगावाट), रातले परियोजना (850 मेगावाट), किरू परियोजना (624 मेगावाट), क्वार परियोजना (540 मेगावाट) शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सलाल और बगलिहार जैसी परियोजनाओं में गाद हटाने (सेडिमेंट फ्लशिंग) और जलाशय प्रबंधन का काम करेगा ताकि भंडारण क्षमता को बहाल किया जा सके, बांध की सुरक्षा बेहतर हो और जलविद्युत दक्षता बढ़ाई जा सके। ये उपाय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इंजीनियरिंग प्रक्रियाएं हैं, न कि नदी के बहाव को बदलने की कोशिशें। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की जल संबंधी चुनौतियां मुख्य रूप से अपर्याप्त जल भंडारण, पुरानी सिंचाई व्यवस्था और जल संसाधनों के अक्षम उपयोग के कारण हैं, न कि भारत की अपस्ट्रीम परियोजनाओं की वजह से। भारत ने दोहराया कि संधि के निलंबन के दौरान वह सिंधु नदी प्रणाली में वैज्ञानिक बेसिन प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और जल सुरक्षा को मजबूत करने के माध्यम से सिंधु जल में भारत के वैध हिस्से के इष्टतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच...

बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 24 घंटों में बातचीत के कई प्रस्ताव दिए हैं और वह विरोध-प्रदर्शन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने दोहराया कि वह बातचीत के लिए तैयार है और प्रदर्शनकारियों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास या कार्यालय में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से यह आंदोलन हो रहा है और इससे जुड़े सभी दूसरे मुद्दों पर भी। बातचीत खुले मन से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर हो सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और जोर दिया कि कोई भी बैठक या तो जंतर-मंतर पर या आपसी सहमति से तय किसी तटस्थ जगह पर होनी चाहिए। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को बातचीत से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे किसी केंद्रीय मंत्री के आवास पर होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे।

सीजेपी ने आज देशव्यापी ...

सीजेपी के मुताबिक, यह प्रदर्शन देशभर में कथित पुलिस बर्बरता के शिकार पीड़ितों के समर्थन में होगा। आयोजकों ने देश के विभिन्न छात्र संघों और अन्य सामाजिक संगठनों से इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करने, आवश्यक अनुमतियां लेने और लॉजिस्टिक्स जुटाने की अपील की है। इस दौरान, विरोध स्थल पर एकत्र भीड़ के सामने छात्रों की मांगों को प्रमुखता से पढ़ा जाएगा। पुलिस कार्रवाई और बर्बरता का सामना करने वाले लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता जताई जाएगी। उल्लेखनीय है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रही सीजेपी ने *संसद चलो* मार्च की घोषणा की थी जिसके बाद 20 जुलाई को हजारों की संख्या में एकजुट हुए छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया था। वे शिक्षा प्रणाली में अनियमितताओं और पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उस दौरान से राजधानी में हालात अनियंत्रित हैं। इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई हैं।

छात्रों के समर्थन में ...

को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा है कि हिंसा और पुलिस कार्रवाई की खबरें बेहद पीड़ादायक हैं। अन्ना हजारे ने पत्र में आगे कहा है कि प्रदर्शनकारियों के असंतोष को कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं, बल्कि समाज की पीड़ा और अपेक्षाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिए बगैर कहा कि अगर किसी मंत्री से इस्तीफा देने को कहा जाता है तो इससे सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि उसकी कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगी। उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों की बात धैर्यपूर्वक सुनने, विश्वास का माहौल बनाने और सकारात्मक संवाद के जरिए समाधान तलाशने का अनुरोध किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीट (नीट) परीक्षा का जिक्र करते हुए हजारे ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रश्न पत्र लीक होने और गंभीर अनियमितताओं के आरोप 2024 में और फिर 2026 में सामने आए। उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा रद्द होने के बाद 22 छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की खबरों पर भी चिंता व्यक्त की। अन्ना हजारे ने यह भी लिखा कि जब भी अनियमितताएं या घोटाले सामने आते थे, तो अक्सर जिम्मेदारी पूरी तरह से निचले स्तर के अधिकारियों पर डाल दी जाती थी, जबकि सरकार सकारात्मक परिणामों का श्रेय खुद ले लेती थी।

राज्य में बाढ़ से हालात गंभीर

11 जिलों की 653164 आबादी प्रभावित, मृतकों की संख्या 44 हुई

गुवाहाटी (हिंस)। असम में लगातार बरसात की वजह से बाढ़ के हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के 22 जुलाई के आंकड़ों के अनुसार, में एक दिन में कुल 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस तरह राज्य में अब तक मरने वालों की कुल संख्या 44 हो गई है। असम में खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली नदियों में बुढ़ीदिहिंग (चेनिमारी, खोवांग), दिखौ (शिवसागर), धनसिरी (नुमालीगढ़), कुशियारा (श्रीभूमि) शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित शिवसागर, चराईदेव एवं जोरहाट जिले का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। असम सरकार के मंत्री बिमल बोरा, केशव महंत, अजंता नेओग एवं विधायक लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। बाढ़ के उच्चतम स्तर से ऊपर बहने वाली नदियों में दिसांग (नांगलामुराघाट) शामिल है। बाढ़ से वर्तमान समय में कुल 11 जिले प्रभावित हुए हैं। इनमें कार्बी आंगलोंग, गोलाघाट, चराईदेव, कामरूप, शिवसागर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, नगांव, धेमाजी, होजाई, कामरूप (मेट्रो) शामिल हैं। बाढ़ से 11 जिलों के 40 राजस्व मंडलों के कुल 939 गांव प्रभावित है। राज्य की कुल 653164 आबादी एवं 24897.27 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कुल 106 राहत शिविर एवं 381 राहत वितरण केंद्र समेत कुल 487 शिविर स्थापित किए गए हैं। राहत शिविरों में 24418 लोग आश्रय लिए हुए हैं। राहत वितरण केंद्रों पर 290826 गैर-शिविर निवासी सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। बाढ़ से 22 जुलाई को 10 लोगों की मौत हो गई। कार्बी आंग्लांग में 1, चराईदेव में 2, शिवसागर में 3, जोरहाट में 3 और धेमाजी में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। इस बीच लापता होने वालों की संख्या शिवसागर जिले में 6 दर्ज की गई है। बाढ़ से प्रभावित जानवरों की कुल संख्या 138965 दर्ज हुई है, जिसमें बड़े 57552, छोटे 38788 एवं मुर्गी-पालन 42625 दर्ज हुए हैं। इस बीच बाढ़ के पानी में कुल 107 जानवर बह गए, जिसमें बड़े 83, छोटे 04 और मुर्गी-पालन 20 बताए गए हैं। बाढ़ में राहत एवं बचाय अभियान में एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं (एफ एंड ईएस), सर्कल कार्यालय/स्थानीय प्रशासन, नागरिक सुरक्षा/प्रशिक्षित स्वयंसेवक और अग्निशमन विभाग जुटा हुआ है। प्रभावित इलाकों में राज्य सरकार ने कुल 11 मेडिकल टीमों को तैनात किया। 56 नावें भी राहत कार्य में जुटी रहीं। बाढ़ में फंसे 8409 लोगों को नावों द्वारा निकाला गया। 35 जानवरों को भी नावों के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित शिवसागर जिले में राहत के कार्य में 1 हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे एक व्यक्ति को सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावितों के बीच राज्य सरकार की ओर से चावल (क्विंटल में): 3637.5254, दाल (क्विंटल में): 691.7632, नमक (क्विंटल में): 1522.3281, मस्टर्ड ऑयल/सरसों का तेल (लीटर में): 14029.133 साथ ही पशुओं का चारा-गेंहू का चोकर (क्विंटल में): 2026.84 और पशुओं का चारा-चावल का चोकर (क्विंटल में): 477.65 राहत सामग्री बांटी गई। बाढ़ से बड़े पैमाने पर सड़क, पुल एवं अन्य आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा है।

राहुल गांधी नीट पेपर लीक मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं : डॉ. रणोज पेगू

गुवाहाटी (हिंस)। असम के शिक्षा मंत्री डॉ. रणोज पेगू ने गुरुवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट पेपर लीक मामले को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और छात्रों की चिंताओं को कांग्रेस की राजनीति का माध्यम बना रहे हैं। असम प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. पेगू ने कहा कि नीट पेपर लीक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों को शीघ्र और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की घोषणा की है, जो छात्रों के हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डॉ. पेगू ने आरोप लगाया कि भाजपा और एनडीए इस मुद्दे पर संसद में व्यापक चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस रचनात्मक बहस से बचते हुए संसद की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रश्नपत्र लीक की समस्या का समाधान राजनीतिकरण से नहीं, बल्कि संस्थागत सुधारों और सभी पक्षों के सहयोग से संभव है। उन्होंने राहुल गांधी से यह भी सवाल किया कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन शासित राज्यों-जम्मू-कश्मीर, झारखंड, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश-में कथित पेपर लीक की घटनाओं पर वे मौन क्यों रहे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान में कई चर्चित पेपर लीक मामले सामने आए थे। डॉ. पेगू ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर राहुल गांधी के हालिया प्रदर्शन की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और वामपंथी दल छात्रों को राजनीतिक लाभ के लिए ढाल बना रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा आईआईटी, आईआईएम, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या के साथ-साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों का भी विस्तार किया गया है, जो छात्रों के हित में महत्वपूर्ण कदम हैं। संवाददाता सम्मेलन में भाजपा असम प्रदेश के महासचिव दिप्लू रंजन शर्मा और अनुप बर्मन, मुख्य प्रवक्ता किशोर उपाध्याय तथा प्रदेश मीडिया विभाग के संयोजक रूपम गोस्वामी भी उपस्थित रहे।

बंगाईगांव में फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले दो गिरफ्तार

बंगाईगांव (हिंस)। असम के बंगाईगांव जिले में पुलिस ने स्वयं को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बंगाईगांव पुलिस ने आज बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलराम चौधरी और बलदेव सिंह के रूप में हुई है। दोनों स्वयं को भारत सरकार के अधीन कथित अपराध अनुसंधान विभाग (क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) का सहायक प्रबंधक और राज्य निदेशक बताकर फर्जी पहचान के जरिए लोगों को झांसे में लेते थे। आरोप है कि उन्होंने कोकिला क्षेत्र के कुछ दूध वितरकों को कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर धन उगाही का प्रयास किया। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर दोनों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से फर्जी पहचान पत्र, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड तथा दो लग्जरी वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आरोपियों का नेटवर्क अन्य राज्यों या क्षेत्रों तक फैला हुआ है या नहीं।

विद्यालय शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के बजट कटौती प्रस्ताव को विपक्ष ने चर्चा के बाद वापस लिया

गुवाहाटी (हिंस)। 16वीं असम विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज 10वें दिन विपक्ष की ओर से विद्यालय शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के बजट कटौती प्रस्ताव पर दो दिनों तक चली चर्चा के बाद विपक्ष ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। जिसके बाद शिक्षा विभाग के बजट को पारित किए जाने का रास्ता साफ हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के अंत में कहा कि दो दिनों में 50 विधायकों ने लंबी चर्चा की। जिससे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय की महत्ता और बढ़ गई है। विपक्षी विधायकों ने यह साफ किया कि कटौती प्रस्ताव लाने का उनका मुख्य उद्देश्य इस विषय की गंभीरता को उजागर करना था, सरकार इस क्षेत्र में और धन का आवंटन करे, उसका वे समर्थन करेंगे। चर्चा के अंत में राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. रनोज पेगू ने इस मुद्दे पर हुई सार्थक एवं लंबी चर्चा का स्वागत करते हुए विधायकों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब देते हुए सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से सभी मुद्दे के समाधान का आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष वाजेद अली चौधरी, एआईयूडीएफ के विधायक मुजिबुर रहमान, टीएमसी के विधायक शेरमान अली अहमद ने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लिया। उल्लेखनीय है कि विद्यालय शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के बजट कटौती प्रस्ताव प्रस्ताव पर 22 जुलाई से आरंभ हुई चर्चा के दूसरे दिन आज कांग्रेस के नुरुल हुदा, डॉ. जय प्रकाश दास, जाकिर हुसैन सिकदर, महिबुर रहमान, नुरुल इस्लाम, वाजेद अली चौधरी, अब्दुर रहीम अहमद, एआईयूडीएफ मुजिबुर रहमान, टीएमसी के शेरमान अली अहमद ने कटौती प्रस्ताव के समर्थन में चर्चा किया। जबकि, भाजपा के प्रकाश चंद्र दास, तुलीराम रांगहांग, पुलक गोहाईं, निसो तेरंग्पी, ऋतुबरन शर्मा, भुवन गाम, पवित्र राभा, विक्टर कुमार दास, शशिकांत दास, किशोर नाथ, हिमांशु शेखर वैश्य एवं अगप के जीवेश राय कटौती प्रस्ताव के विरोध में चर्चा में हिस्सा लिया।

नगालैंड में बादल फटने की घटना का वैज्ञानिक अध्ययन होगा : मुख्यमंत्री

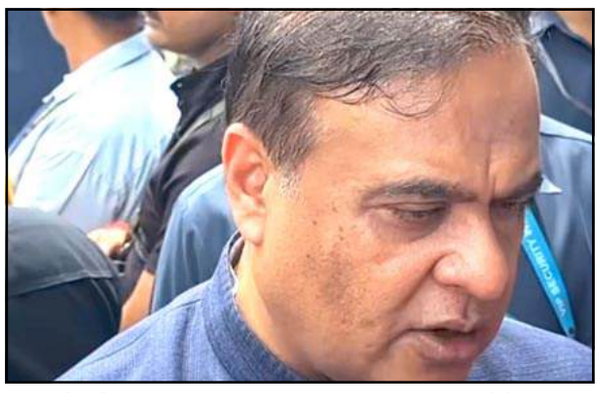

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि नगालैंड में हुई बादल फटने की घटना के प्रभाव तथा उससे उत्पन्न समग्र स्थिति का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा। मुख्यमंत्री बीती रात जोरहाट में टूटे हुए तटबंध का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बाढ़ की स्थिति सामान्य होने के बाद उपग्रह चित्रों के माध्यम से पूरे प्रभावित क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वैज्ञानिक अध्ययन से आपदा के कारणों और उसके प्रभाव का सटीक आकलन करने में मदद मिलेगी।

लाहोवाल में तीन युवकों पर फायरिंग गंभीर रूप से घायल

डिब्रूगढ़ (हिंस)। असम के लाहोवाल के घोड़ामारा क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने तीन युवकों पर गोलीबारी कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, तीनों युवक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान एक लग्जरी वाहन में सवार अज्ञात बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके पैरों में गोली मारकर फरार हो गए। घायलों की पहचान रंटू गोगोई, दीपज्योति गोगोई और मिथु गोगोई के रूप में हुई है। तीनों को गंभीर हालत में डिब्रूगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की पहचान और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

एपीसीसी अध्यक्ष गौरव गोगोई ने असम बाढ़ राहत में देरी का लगाया आरोप

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने गुरुवार को राज्य सरकार पर बाढ़ से प्रभावित लोगों को आपातकालीन राहत पहुंचाने में *बहुत ज्यादा देरी* का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राशन, पीने का साफ पानी और साफ-सफाई का सामान जैसी जरूरी चीजें लोगों तक समय पर नहीं पहुंच रही हैं। बाढ़ को *बड़ा मानवीय संकट* बताते हुए, गोगोई ने सरकार से मरने वालों की संख्या का *सही ब्यौरा* देने और बिना किसी देरी के हर प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचाने की अपील की। गोगोई ने सोशल मीडिया *एक्स* पर एक पोस्ट में कहा कि आज तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और लाखों लोग सम्मानजनक जीवन नहीं जी पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित लोगों को आपातकालीन राशन, पीने का साफ पानी, फिनाइल, कपड़े और ब्लीचिंग पाउडर बांटने में *बहुत ज्यादा देरी* हुई है। लोकसभा में विपक्ष के उप-नेता और कांग्रेस नेता ने बताया कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों- जोरहाट, शिवसागर और चराईदेव का दौरा किया, जहां उन्होंने *नुकसान का पैमाना और स्थानीय प्रशासन की ओर से मदद की कमी को खुद देखा*। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को तुरंत यह बताना चाहिए कि कितने लोगों की मौत हुई है और यह पक्का करना चाहिए कि बिना किसी देरी के हर प्रभावित घर तक राहत पहुंचे। गोगोई ने केंद्र सरकार से तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम भेजने की भी अपील की, जो लोगों को क्षतिग्रस्त घरों को फिर से बनाने और बाढ़ से बाधित खेती के काम को दोबारा शुरू करने में मदद कर सके। उन्होंने राहत कार्यों को आयोजित करने और हर दिन सैकड़ों परिवारों को खाना खिलाने के लिए *युवाओं और जेन जी* के कई स्वयंसेवी समूहों की तारीफ भी की। गोगोई ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से ऊपरी असम के बाढ़ प्रभावित गांवों और परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने की अपील की।

दिनभर के लिए विधानसभा से निलंबित किए गए अखिल गोगोई

गुवाहाटी (हिंस)। असम विधानसभा में कार्रवाई के दौरान निर्दलीय (राइजर दल) विधायक अखिल गोगोई को आज दिनभर के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। अखिल गोगोई ने राज्य में आई बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित ऊपरी असम के शिवसागर जिला समेत अन्य जिलों के संबंध में सभा स्थगन का प्रस्ताव पेश करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रंजीत दास से 2 मिनट का समय मांगा था। अध्यक्ष ने उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया। समय बीत जाने के बाद भी काफी देर तक अखिल गोगोई से बार-बार अध्यक्ष के आग्रह करने के बावजूद नहीं बैठे। गोगोई ने सदन में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाने पर वह हंगामा करने लगे। गोगोई बेहद गुस्से में अध्यक्ष पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया। इतना नहीं टेबल पर चढ़कर नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष पर समय न देने का आरोप लगाया। अध्यक्ष दास ने कहा कि आपके (गोगोई) द्वारा मांगी गई समय सीमा के तहत 2.40 मिनट तक बोल चुके हैं। ऐसे में पूर्व निर्धारित कार्रवाई को अब आगे बढ़ाया जाएगा। गोगोई के टेबल पर चढ़कर हंगामा करने वाले आचरण से पूरा सदन आवाक रह गया। अध्यक्ष द्वारा बार-बार शांत होने की अपील जब काम नहीं आई तो अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल के जरिए अखिल को पूरे दिनभर के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबितर कर दिया गया। सदन से बाहर आने के बाद अखिल गोगोई ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई की कड़ी आलोचना की।

बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत सामग्री और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की समीक्षा, मंत्री कौशिक राय ने दिए निर्देश

गुवाहाटी (हिंस)। असम के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कौशिक राय ने गुरुवार को ऊपरी असम और उत्तर असम के प्रमुख बाढ़ प्रभावित जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राहत सामग्री के उठाव एवं वितरण, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, भंडारण तथा बाजार मूल्य की समीक्षा की। बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने सभी जिला प्रशासन को राहत सामग्री समय पर प्रभावित लोगों तक पहुंचाने और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तरीय टास्क फोर्स को 24 घंटे सक्रिय रहकर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी निगरानी रखने तथा कहीं भी अनुचित मूल्य वृद्धि होने पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कौशिक राय ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है कि राहत सामग्री और आवश्यक सेवाएं बिना किसी विलंब के प्रत्येक प्रभावित परिवार तक पहुंचें। बैठक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बिस्वरंजन समल ने शेष खरीदे गए धान की शीघ्र मिलिंग कर चावल को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सौंपने के निर्देश दिए, ताकि भंडारित अनाज को नुकसान से बचाया जा सके। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, एफसीआई, एएफडीयूसीएल तथा संबंधित जिलों के उपायुक्त भी उपस्थित रहे।

गुवाहाटी में नेशनल हाईवे-27 पर जलभराव बरकरार

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी के बोरागांव क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर गुरुवार को भी भारी जल जमाव हो गया, जिसके चलते सड़क का एक हिस्सा अब भी जलमग्न है। जलभराव के बावजूद लोग और वाहन चालक जोखिम उठाकर इस मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं। लगातार जलभराव के कारण यातायात प्रभावित है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कोकराझाड़ में बीईईओ और सीआरसीसी के लिए जनगणना 2027 (चरण-वन) पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

कोकराझाड़ (विभास)। जिला प्रशासन, कोकराझाड़ द्वारा आगामी डिजिटल जनगणना अभ्यास की तैयारी को मजबूत करने के लिए साइंस कॉलेज, कोकराझाड़ में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (बीईईओ) और क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयकों (सीआरसीसी) के वास्ते जनगणना 2027 (चरण-वन) पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कोकराझाड़ के जिला आयुक्त, पंकज चक्रवर्ती ने की। उन्होंने जनगणना 2027 के चरण-वन के तहत प्रक्रियाओं, भूमिकाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की स्पष्ट समझ के साथ प्रमुख शैक्षणिक पदाधिकारियों को सुसज्जित करने में इस जागरूकता पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, जिला आयुक्त ने शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच परिचालन दिशानिर्देशों का प्रचार-प्रसार करने, जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने और जनगणना प्रक्रिया के दौरान प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने में बीईईओ और सीआरसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग आवश्यक सहायता प्रदान करके और जमीनी स्तर के कर्मियों के साथ सुचारू संचार सुनिश्चित करके जनगणना के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने आगे इस बात पर बल दिया कि जनगणना 2027 के निर्बाध निष्पादन और पूरे जिले में सटीक जमीनी स्तर पर डेटा संग्रह सुनिश्चित करने में शैक्षणिक अधिकारियों और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी सहायक होगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को डिजिटल जनगणना प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रोटोकॉल और जनगणना 2027 के चरण-वन के सफल संचालन का समर्थन करने में उनकी जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशील बनाना था। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ पूरे जिले के ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयक उपस्थित रहे।

संपादकीय

पीएम आवास तक तकरार

पेपरलीक आंदोलन, तकरार और विरोध-प्रदर्शन प्रधानमंत्री आवास की दहलीज तक पहुंच गया। यकीनन यह चौंकाने वाला यथार्थ है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ स्वीकार नहीं है। यह दंडनीय अपराध है। राजधानी दिल्ली में आंदोलन के स्थान चिह्नित हैं। पेपरलीक और युवाओं के भविष्य पर कोई तकरार है, तो उसके लिए संसद का मंच है। कमोबेश संसद में विपक्ष हंगामा करने, नारेबाजी, हुल्लड़बाजी से बाज आएगा, तो सदन में इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। यह आश्वासन प्रधानमंत्री मोदी तक ने दिया है और एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए भी आश्वस्त किया है कि पेपरलीक के 'माफिया' को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। आरोपित जेल में भी हैं। संसद सत्र जारी है, लेकिन कार्यवाही बंजर है, क्योंकि विपक्ष को हंगामा करना ही विशेषाधिकार लगता है। बहरहाल संसद के दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष-राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे-ने स्थापित कानून को तोड़ा है। खड़गे का सरकारी आवास 10, राजाजी मार्ग है, जो प्रधानमंत्री आवास से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। 21 जुलाई को खड़गे का 84वां जन्मदिन था, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के अलावा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और अन्य महत्वपूर्ण चेहरे खड़गे के आवास पर जुटे थे। संभवतः वहीं रणनीति तय हुई और कांग्रेसी पैदल चल कर ही प्रधानमंत्री आवास की दहलीज तक पहुंच गए। दलील दी गई कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं, लिहाजा हम उनसे मिलने आए हैं। यह कुतर्क के अलावा कुछ भी नहीं। यह धरना सुरक्षा-व्यवस्था का घोर उल्लंघन था। चूंकि अधिकतर सांसद थे, लिहाजा वे संसद भवन में ही निश्चित स्थान पर धरना और नारेबाजी कर सकते थे। प्रधानमंत्री आवास की वह दहलीज 'उच्चतम सुरक्षा' क्षेत्र है, लिहाजा 'अति संवेदनशील' भी है। वहां से प्रधानमंत्री का काफिला ही आ-जा सकता है। वीवीआईपी मेहमान भी उसी रास्ते से प्रधानमंत्री से मुलाकात करने आते हैं। सवाल है कि क्या पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इस धरने की भनक तक नहीं लगी? प्रधानमंत्री को पल-पल की खबर दी जाती है, फिर इतनी चूक कैसे हो गई? बहरहाल आजादी के बाद सिर्फ दो बार प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनबाजी की गई है, लेकिन दोनों बार 'नेता प्रतिपक्ष' शामिल नहीं थे। 1999 में आईसी-814 विमान अपहरण के वक्त पीड़ित, चिंतित जनता प्रधानमंत्री आवास तक पहुंची थी, क्योंकि विमान में कई यात्री सवार थे और अपहरण आतंकियों ने किया था। तब देश के प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी थे। दूसरी बार, 2012 में अन्ना हजारे आंदोलन के समय युवाओं की भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया था। डॉ. मनमोहन सिंह तब देश के प्रधानमंत्री थे। दरअसल किसी भी विवाद, मुद्दे, समस्या, आपदा, कांड का न्यायिक निपटारा प्रधानमंत्री आवास पर धरना देकर हासिल नहीं किया जा सकता। मौजूदा कांग्रेसी धरना राजनीतिक अराजकता, मेरी मर्जी वाला अहंकार और पेपरलीक पर विभाजित राजनीति का स्पष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री दफ्तर में राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविन्द मोहन दो बार धरनास्थल तक आए और राहुल गांधी से संवाद किया, उन्हें प्रधानमंत्री आवास की दहलीज की संवेदनशीलता समझाई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं माने। अपनी बात से मुकरते रहे और कई बार जवाब दिया-'मेरी मर्जी..।' देश किसी व्यक्ति की मनमर्जियों से नहीं चला करता। अंततः पुलिस के जवानों ने हल्का बलप्रयोग करते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को टांगते हुए उठाया, हिरासत में लिया और बस में ठेल कर छत्रसाल स्टेडियम ले गए। देर रात उन्हें रिहा कर दिया गया। प्रियंका गांधी को भी जबरन उठा कर बस में बिठाया गया। मंदिर मार्ग थाने में उनसे मिलने मां सोनिया गांधी गईं। उन्हें भी रिहा कर दिया गया। दरअसल कांग्रेस सोच रही है कि पेपरलीक पर मोदी सरकार बैकफुट पर है। यह व्यापक वोट बैंक का भी मुद्दा है, लिहाजा राहुल गांधी 'गूंज' नाम से एक अभियान छात्रों के लिए चला रहे हैं। इसी दौरान जून में 'कॉकरोच जनता पार्टी' प्रकट हो गई, तो उसके युवा नेतृत्व ने भी पेपरलीक को बुनियादी मुद्दा बनाया। विपक्ष दोनों ओर बंटा हुआ है।

पेपरलीक और युवाओं के भविष्य पर कोई तकरार है, तो उसके लिए संसद का मंच है। कमोबेश संसद में विपक्ष हंगामा करने, नारेबाजी, हुल्लड़बाजी से बाज आएगा, तो सदन में इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। यह आश्वासन प्रधानमंत्री मोदी तक ने दिया है और एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए भी आश्वस्त किया है कि पेपरलीक के 'माफिया' को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। आरोपित जेल में भी हैं। संसद सत्र जारी है, लेकिन कार्यवाही बंजर है, क्योंकि विपक्ष को हंगामा करना ही विशेषाधिकार लगता है। बहरहाल संसद के दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष-राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे-ने स्थापित कानून को तोड़ा है। खड़गे का सरकारी आवास 10, राजाजी मार्ग है, जो प्रधानमंत्री आवास से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। 21 जुलाई को खड़गे का 84वां जन्मदिन था, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के अलावा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और अन्य महत्वपूर्ण चेहरे खड़गे के आवास पर जुटे थे।

रेडियो प्रसारण तकनीक के विकास के साथ ही 1922 में बीबीसी का गठन हो चुका था

सौंवे सोपान की ओर भारतीय प्रसारण

उमेश चतुर्वेदी

आज का दिन भारतीय प्रसारण के इतिहास में विशेष महत्व है। ठीक 99 साल पहले 23 जुलाई 1927 को मुंबई में भारत में पहले व्यवस्थित और संस्थानिक प्रसारण की शुरूआत हुई थी। इस लिहाज से भारतीय प्रसारण आज से अपनी शतकीय सोपान की ओर बढ़ रहा है। इस शतकीय यात्रा में रेडियो की तकनीक में बहुत बदलाव हुआ है। पारंपरिक मीडियम वेब से लेकर शॉर्ट वेब होते हुए रेडियो अब एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल के साथ ही डिजिटल दौर में प्रवेश कर गया है। मीडिया के चरित्र में भी सौ साल में बहुत बदलाव हो गया है, लेकिन रेडियो आज भी संवाद और मनोरंजन के सहज संचार माध्यम के रूप में जिंदा है। आसानी से हर जगह उपलब्धता और विशेष तकनीक की वजह से आपदा के क्षणों में संचार के दूसरे माध्यमों की तुलना में रेडियो अब भी सबसे ज्यादा प्रभावी माध्यम बना हुआ है। समुद्री तूफानों, सुनामी, कश्मीर घाटी की बाढ़ आदि मौकों पर संवाद के लिए रेडियो ने अपनी ताकत और उपादेयता को बार-बार साबित किया है। देश से माओवादी और नक्सली आतंक का खात्मा हो चुका है, लेकिन एक दौर में विशेषकर बस्तर के नक्सली इलाकों में नक्सलियों से संवाद के लिए रेडियो का ही इस्तेमाल किया जाता था। भारतीय वायु सेना भर्ती इसे संयोग ही कहेंगे कि जब रेडियो प्रसारण तकनीक का आविष्कार हुआ, उन दिनों देश गुलामी की जंजीरों से बंधा था। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में भी प्रसारण की प्रेरणा ब्रिटेन से मिली। रेडियो प्रसारण तकनीक के विकास के साथ ही 1922 में बीबीसी का गठन हो चुका था। हालांकि ब्रिटेन में इसके पहले ही निजी और शौकिया प्रसारण की शुरूआत हो चुकी थी। इसका असर भारत पर भी पड़ा। भारत में भी 1920 से 1926 के बीच तत्कालीन बंबई और कलकत्ता में रेडियो क्लबों की शुरूआत हुई। उन क्लबों ने अपने तरीके से प्रसारण के किंचित सफल और ज्यादातर असफल प्रयास भी किये। उन दिनों भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इर्विन थे। अखबारों की तुलना में रेडियो प्रसारण की अहमियत और प्रभाव को इर्विन समझते थे। शायद यही वजह रही कि भारत में 1926 में गठित इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का गठन हुआ। कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक बांबे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब ने जून 1923 में पहला रेडियो प्रसारण किया। इसके करीब पांच महीने बाद नवंबर 1923 में कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना हुई। ऐसे ही प्रयास तत्कालीन मद्रास में भी हुए। लेकिन पहला व्यवस्थित और संस्थानिक रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने 23 जुलाई 1927 को मुंबई से किया था। इसी वजह से भारत हर साल 23 जुलाई को प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके महीनेभर बाद 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता से बांग्ला में प्रसारण शुरू हुआ। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी छह लाख की पूंजी से शुरू की गई थी। कंपनी ने रेडियो प्रसारण के लिए अंग्रेज सरकार से 13 सितंबर 1926 को करार हुआ, जिसके तहत उसने प्रसारण शुरू किया। कंपनी को पूंजी में से साढ़े चार लाख दोनों रेडियो केंद्रों की स्थापना में ही खर्च हो गए। तब आमदनी का स्रोत रेडियो लाइसेंस फीस थी, जो प्रति रेडियो दस रूपए थी। बहुत कोशिशों के बावजूद सिर्फ आठ हजार ही लाइसेंस दिए जा सके। तब प्रसारण डेढ़-डेढ़ किलोवाट के ट्रांसमीटरों से बमुश्किल तीस मील के ही दायरे में हो पा रहा था, लिहाजा रेडियो का प्रसार नहीं बढ़ा। कंपनी को रेडियो प्रसारण के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही थी। लिहाजा यह कंपनी 1930 में ही बंद हो गई। भारत में आधुनिक प्रसारण की ठोस बुनियाद रखने का श्रेय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो और ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कंपनी के पूर्व प्रसारक लायनेड फील्डेन को जाता है। लिनलिथगो की पहल पर उद्योग और श्रम विभाग के अधीन अप्रैल 1930 में इंडियन स्टेट ब्राडकास्टिंग सर्विस की शुरूआत हुई। इसे रेडियो प्रसारण को नया रूप देना था। इसके बाद अगस्त 1935 में लायनेड फील्डेन को इस सर्विस का कंट्रोलर नियुक्त किया गया। फील्डेन को यह नाम पसंद नहीं आ रहा था। फील्डेन ने अपनी पुस्तक 'नेचुरल बेंट' में लिखा है कि उन्होंने लिनलिथगो को सुझाया कि ब्रॉडकास्टिंग शब्द कठिन है, जो आसानी से भारतीयों की जुबान पर नहीं चढ़ पाएगा। फिर यह नाम भारत सरकार अधिनियम के अनुकूल नहीं है। लिहाजा उन्होंने इसे 'ऑल इंडिया रेडियो' करने का सुझाव दिया। जिसे लिनलिथगो ने स्वीकार कर लिया। इसी के बाद आठ जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से दिल्ली के अलीपुर के छह कमरों के एक घर से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। कुछ महीने बाद यह दफ्तर दिल्ली के संसद मार्ग स्थित नए बने प्रसारण भवन में आया और तब से लेकर अब तक दिल्ली केंद्र का प्रसारण वहीं से हो रहा है। तीन मई 2023 से ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के नाम से जाना जा रहा है। वैसे ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम गांधी जयंती के दिन 1957 में दिया गया, जिसे अगले दिन से लागू किया गया। आकाशवाणी का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में आकाश से आने वाली आवाज या देववाणी के रूप में मिलता है। वैसे आकाशवाणी के नाम से मैसूर के विद्वान एमवी गोपालस्वामी ने 10 सितंबर 1935 से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। यह प्रसारण केंद्र मैसूर राजमहल से कुछ सौ मीटर दूर स्थित है। आकाशवाणी का जिक्र 1938 में कलकत्ता में शॉर्ट वेब के प्रसारण की शुरूआत के वक्त भी हुआ। तब प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने गुरूदेव रवींद्र नाथ टैगोर से एक कविता मांगी थी। टैगौर ने बांग्ला की जो कविता दी, उसमें रेडियो के लिए आकाशवाणी शब्द का प्रयोग हुआ है। इसे संयोग ही कहेंगे कि जिस समय देश में रेडियो का विस्तार हो रहा था, उन्हीं दिनों स्वाधीनता आंदोलन चरम पर था। उसी दौरान 1942 में डॉक्टर राममनोहर लोहिया और ऊषा मेहता की अगुआई में मुंबई से कांग्रेस रेडियो और रंगून से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद रेडियो का प्रसारण शुरू किया। बोस जहां अपने रेडियो के जरिए भारतीय जनता से संवाद कर रहे थे, वहीं कांग्रेस रेडियो भूमिगत ढंग से चलाया जा रहा था। जिसके जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को सूचनाएं दी जा रही थीं। उन्हीं दिनों अंग्रेज सरकार ने देश में नौ रेडियो प्रसारण केंद्र स्थापित किए। ये केंद्र दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, त्रिचिरापल्ली, चेन्नई, ढाका, पेशावर और लाहौर में थे। बंटवारे के बाद भारत के हिस्से छह रेडियो स्टेशन आए, जबकि पाकिस्तान को ढाका, पेशावर और लाहौर स्टेशन मिले। आजादी के बाद देश के पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सरदार पटेल को मिली। उन्हें रेडियो की महत्ता का भान था। इसीलिए उन्होंने रेडियो के तेज विकास की नींव रखी। आजादी के बाद पहला रेडियो स्टेशन 16 जुलाई 1948 को शुरू हुआ। जिसका उद्घाटन पटेल ने किया था। स्वाधीन भारत में रेडियो का चरित्र और लक्ष्य क्या होगा, इसका संकेत सरदार पटेल के उस उद्घाटन भाषण में दिखता है। सार्वजनिक प्रसारक के रूप में रेडियो के लक्ष्य को एक तरह से मद्रास प्रांत के तत्कालीन प्रीमियर सी राजगोपालाचारी ने 1938 में ही रख दिया था। 16 जून 1938 को मद्रास रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करते हुए राजगोपालाचारी ने रेडियो को लोक जागरण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया था। इसके साथ ही उन्होंने संचार के तेज माध्यम के रूप में रेडियो का शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए करने पर जोर दिया था। यहां यह बताना जरूरी नहीं है कि सार्वजनिक प्रसारक के रूप में रेडियो आज भी यह भूमिका बखूबी निभा रहा है। भारतीय इतिहास में रेडियो कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। तीन जून 1947 को भारत विभाजन की योजना की देश को जानकारी रेडियो के जरिए ही मिली। तब माउंट बेटन, नेहरू, जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह ने रेडियो के ही माध्यम से अपने विचार रखे थे। 14-15 अगस्त 1947 की दरम्यानी रात को भारत की आजादी के बाद नेहरू के प्रसिद्ध भाषण 'ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' को देश ने रेडियो के जरिए सुना था। गांधी जी जिंदगी में सिर्फ एक बार 12 नवंबर 1948 को दिल्ली केंद्र आए थे। यहां से उन्होंने रेडियो के जरिए कुरूक्षेत्र स्थित शरणार्थियों को संबोधित किया था।

मुंबई में भारत में पहले व्यवस्थित और संस्थानिक प्रसारण की शुरूआत हुई थी। इस लिहाज से भारतीय प्रसारण आज से अपनी शतकीय सोपान की ओर बढ़ रहा है। इस शतकीय यात्रा में रेडियो की तकनीक में बहुत बदलाव हुआ है। पारंपरिक मीडियम वेब से लेकर शॉर्ट वेब होते हुए रेडियो अब एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल के साथ ही डिजिटल दौर में प्रवेश कर गया है। मीडिया के चरित्र में भी सौ साल में बहुत बदलाव हो गया है, लेकिन रेडियो आज भी संवाद और मनोरंजन के सहज संचार माध्यम के रूप में जिंदा है। आसानी से हर जगह उपलब्धता और विशेष तकनीक की वजह से आपदा के क्षणों में संचार के दूसरे माध्यमों की तुलना में रेडियो अब भी सबसे ज्यादा प्रभावी माध्यम बना हुआ है। समुद्री तूफानों, सुनामी, कश्मीर घाटी की बाढ़ आदि मौकों पर संवाद के लिए रेडियो ने अपनी ताकत और उपादेयता को बार-बार साबित किया है।

देश | दुनीया से

स्व-देखभालः स्वस्थ व्यक्ति से विश्वकल्याण की भारतीय दृष्टि

मानव सभ्यता के विकास के इस दौर में जितनी तीव्र गति से विज्ञान, तकनीक और भौतिक संसाधनों का विस्तार हुआ है, उतनी ही तेजी से मनुष्य तनाव, अवसाद, असंतुलित जीवनशैली और अनेक नई बीमारियों के जाल में भी उलझता गया है। विडम्बना यह है कि आज मनुष्य के पास संसार की लगभग हर वस्तु के लिए समय है, लेकिन स्वयं के लिए समय नहीं है। वह परिवार, समाज, व्यवसाय और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन तो कर रहा है, परंतु अपने शरीर, मन और आत्मा के प्रति उत्तरदायित्व को लगातार उपेक्षित करता जा रहा है। ऐसे समय में प्रतिवर्ष 24 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्व-देखभाल दिवस केवल स्वास्थ्य जागरूकता का अभियान नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, सार्थक और मानवीय बनाने का वैश्विक संदेश है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ समाज, समृद्ध राष्ट्र और शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण तभी संभव है, जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की देखभाल को अपना प्रथम कर्तव्य माने। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2011 में इंटरनेशनल सेल्फ-केयर फाउंडेशन ने की। स्व-देखभाल केवल किसी विशेष दिन या अवसर का विषय नहीं, बल्कि चौबीस घंटे और सप्ताह के सातों दिन अपनाई जाने वाली जीवनशैली है।

स्व-देखभाल का अर्थ केवल बीमारी से बचना या समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है-अपने शरीर, मन, भावनाओं, विचारों और आत्मा की समग्र सुरक्षा एवं संवर्धन करना। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि यदि व्यक्ति अपनी जीवनशैली को संतुलित बनाए, पौष्टिक भोजन ग्रहण करे, नियमित व्यायाम करे, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखे और रोगों की रोकथाम को प्राथमिकता दे, तो स्वास्थ्य प्रणालियों पर अनावश्यक दबाव कम होगा और समाज अधिक स्वस्थ बनेगा। किंतु केवल चिकित्सकीय उपाय पर्याप्त नहीं हैं। मनुष्य का स्वास्थ्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक उसके भीतर मानसिक संतुलन, नैतिक चेतना और आध्यात्मिक

शांति का विकास न हो। वर्तमान समय की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि मनुष्य बाहर से जितना आधुनिक हुआ है, भीतर से उतना ही अशांत होता गया है। प्रतिस्पर्धा, उपभोगवाद और अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं ने जीवन की सहजता को छीन लिया है। तनाव अब केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिवारों, विद्यालयों और बच्चों तक पहुँच गया है। यही कारण है कि आज मानसिक रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग और अवसाद जैसी समस्याएँ वैश्विक चिंता का विषय बन चुकी हैं। ऐसे समय में स्व-देखभाल केवल व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व भी है। भारत की दृष्टि से देखें तो स्व-देखभाल का विचार कोई नया नहीं है। यह हमारी सनातन सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग रहा है। भारत ने हजारों वर्ष पहले ही यह उद्घोष किया था-'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' अर्थात्शरीर ही सभी श्रेष्ठ कार्यों का प्रथम साधन है। भारतीय चिंतन ने स्वास्थ्य को केवल शरीर की निरोगता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलन को भी स्वास्थ्य का अनिवार्य आधार माना। आयुर्वेद, योग, ध्यान, प्राणायाम, उपवास, संयम, अहिंसा और सात्त्विक जीवनशैली इसी समग्र दृष्टि के अंग हैं। यही कारण है कि भारत में स्वास्थ्य और अध्यात्म कभी अलग-अलग विषय नहीं रहे, बल्कि एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। आज जब संपूर्ण विश्व योग को अपनाकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब यह स्मरण करना आवश्यक है कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। योग शरीर को स्वस्थ करता है, प्राणायाम मन को संतुलित करता है, ध्यान चेतना को निर्मल बनाता है और अध्यात्म जीवन को दिशा देता है। इसी प्रकार जैन दर्शन का संयम, अहिंसा, प्रेक्षाध्यान और आत्मनिरीक्षण, बौद्ध दर्शन का विपश्यना मार्ग तथा गीता का समत्व योग मनुष्य को भीतर से स्वस्थ बनाते हैं। भारत की यही आध्यात्मिक परंपरा आज विश्व के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। यदि हम वास्तव में स्व-देखभाल को जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हमें इसे केवल स्वास्थ्य संबंधी गतिविधि न मानकर जीवन-दर्शन के रूप में स्वीकार करना होगा। प्रातःकाल का भ्रमण, नियमित योगाभ्यास, ध्यान, स्वाध्याय, आध्यात्मिक प्रवचनों का श्रवण, संतुलित एवं सात्त्विक भोजन, पर्याप्त नींद, डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से बचाव, प्रकृति के साथ समय बिताना, स्व-संवाद, आत्म-साक्षात्कार तथा प्रतिदिन आत्मचिंतन-ये सभी स्व-देखभाल के ऐसे सूत्र हैं जो व्यक्ति को भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर स्वस्थ बनाते हैं। यह जीवनशैली न केवल रोगों से बचाती है, बल्कि मनुष्य को सकारात्मक, करुणामय और संतुलित भी बनाती है। आज विकसित भारत का जो स्वप्न देश देख रहा है, उसकी आधारशिला केवल आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। यदि राष्ट्र को वास्तव में विकसित बनाना है तो उसके नागरिकों का स्वस्थ, अनुशासित, संस्कारित और जागरूक होना अनिवार्य है। बीमार और तनावग्रस्त समाज कभी समृद्ध राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। स्वस्थ नागरिक ही उत्पादक होंगे, रचनात्मक होंगे और राष्ट्र निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे।

आप का | नजरीया

पहचान बदलता हिमाचल

पहचान बदलता हिमाचल अपनी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों, विकास मॉडल, आर्थिक संभावनाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सहारे क्षमतावान हो रहा है, तो नए अवसरों की पैरवी निवेश के बाजार ढूंढ रही है। जाहिर है इसी उद्देश्य से चंडीगढ़ की बैठक में एक रूपरेखा बनी है। द इंडस इंटरप्रेन्योर्स (टी आई आई) की लीडरशिप कन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने निवेशक बिरादरी से आह्वान किया है तो आशा यह है कि निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से आने वाली औद्योगिक नीति कारगर सिद्ध होगी। इधर प्रदेश के भीतर वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट्स पहचानते हुए सरकार का आरंभिक खाका 36 उत्पादों की फेहरिस्त में काम कर रहा है। कृषि, बागबानी, ग्रामीण, कला, हस्तशिल्प और परंपरावादी उत्पादों में हर जिला कम से कम तीन उत्पादों की श्रेष्ठता में आगे आ रहा है। इसके साथ कृषि-बागबानी विश्वविद्यालय व संबंधित विभागों के लक्ष्य भी सामने आ रहे हैं, तो हिमाचल के पर्यटन क्षेत्र के जरिए एक मार्किट विकसित हो रही है। हालांकि यह सूची पूर्ण नहीं है और कई और उत्पाद इसमें जुड़ सकते हैं। जाहिर है अब तक कृषि उपज विपणन बोर्ड, हथकरघा निगम-हिम बुनकर के आउटलेट, हिम ईरा, माय पहाड़ी दुकान व शी हॉट जैसे केंद्रों से दुनिया हिमाचली उत्पादों की खरीददारी कर रही है। जरूरत है एक ब्रांड और एक छत के नीचे सारी शॉपिंग हो। प्रदेश के मंदिरों का प्रसाद भी अपनी उत्पादन की खरीद क्षमता का उज्ज्वल उदाहरण है। मंदिर उत्पादों की संभावना देखी जाए, तो धार्मिक स्थलों की आर्थिकी इन्हीं पर निर्भर है। कांगड़ा-चंबा का धूप, ज्वालाजी के पेड़े, दियोटसिद्ध के रोट और पूजा पद्धति से जुड़े बाजारों की क्षमता समझी जाए, तो धार्मिक स्थल औद्योगिक व सांस्कृतिक उत्पादन के रूप में विकसित हो सकते हैं। मसलन अगर दियोटसिद्ध के रोट को सभी मंदिरों का आधिकारिक प्रसाद बना दें, तो रोजाना कई ट्रक आपूर्ति करनी पड़ेगी। इसी तरह धूप, झंडे, फूल, पेड़े, पीतल का सामान तथा अन्य चढ़ावे की वस्तुओं के केंद्रीय उत्पादन व विपणन की पहल हो तो मंदिरों की आय बढ़ जाएगी। प्रदेश के कम से कम एक दर्जन बड़े मंदिरों के आसपास के दस-बारह किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में परिक्रमा तथा धार्मिक शहर विकसित करने का मास्टर प्लान बनाएं, तो निवेश बढ़ेगा-आर्थिकी फले फूलेगी। हिमाचल में निवेश से पहले टी सी पी के तहत विकास योजनाएं बनानी होंगी। उदाहरण के लिए फोरलेन के नक्शे पर कुछ निवेश स्थल विकसित करके हम इसे पर्यटन वृद्धि दर के हिसाब से टूरिज्म कोरिडोर रेखांकित कर सकते हैं। मनोरंजन की दृष्टि से पूरे राज्य में मनोरंजन-वाटर पार्क, साइंस सिटी, हॉट बाजार, हाई वे पर्यटन सुविधाएं और पर्यटक गांव विकसित कर सकते हैं। हिमाचल में रज्जु मार्ग, फर्निकुलर प्रोजेक्ट, मॉल, अस्पताल तथा आधुनिक बाजार एवं बस स्टैंड विकसित करने को निवेश प्रोत्साहित करना होगा। अभी हाल ही में नगर निगम चुनाव के विजन डाक्यूमेंट में कई संकल्प सामने आए जहां शहरी विकास को निजी निवेश की जरूरत है। मसलन धर्मशाला नगर निगम के तहत चरान से भागसू तक फर्निकुलर रोप वे जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजना में कोई निवेशक भागीदार हो सकता है। हिमाचल में फिलहाल कई छोटे-बड़े स्वाभाविक निवेशक या व्यापारी हैं। इन्हें आगे बढ़कर निवेश के नए अवसर दिए जाएं, तो हर शहर और हर गांव तक निवेश होगा।

आर्थिक संभावनाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सहारे क्षमतावान हो रहा है, तो नए अवसरों की पैरवी निवेश के बाजार ढूंढ रही है। जाहिर है इसी उद्देश्य से चंडीगढ़ की बैठक में एक रूपरेखा बनी है। द इंडस इंटरप्रेन्योर्स (टी आई आई) की लीडरशिप कन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने निवेशक बिरादरी से आह्वान किया है तो आशा यह है कि निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से आने वाली औद्योगिक नीति कारगर सिद्ध होगी। इधर प्रदेश के भीतर वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट्स पहचानते हुए सरकार का आरंभिक खाका 36 उत्पादों की फेहरिस्त में काम कर रहा है। कृषि, बागबानी, ग्रामीण, कला, हस्तशिल्प और परंपरावादी उत्पादों में हर जिला कम से कम तीन उत्पादों की श्रेष्ठता में आगे आ रहा है। इसके साथ कृषि-बागबानी विश्वविद्यालय व संबंधित विभागों के लक्ष्य भी सामने आ रहे हैं, तो हिमाचल के पर्यटन क्षेत्र के जरिए एक मार्किट विकसित हो रही है। हालांकि यह सूची पूर्ण नहीं है और कई और उत्पाद इसमें जुड़ सकते हैं। जाहिर है अब तक कृषि उपज विपणन बोर्ड, हथकरघा निगम-हिम बुनकर के आउटलेट, हिम ईरा, माय पहाड़ी दुकान व शी हॉट जैसे केंद्रों से दुनिया हिमाचली उत्पादों की खरीददारी कर रही है। जरूरत है एक ब्रांड और एक छत के नीचे सारी शॉपिंग हो। प्रदेश के मंदिरों का प्रसाद भी अपनी उत्पादन की खरीद क्षमता का उज्ज्वल उदाहरण है। मंदिर उत्पादों की संभावना देखी जाए, तो धार्मिक स्थलों की आर्थिकी इन्हीं पर निर्भर है। कांगड़ा-चंबा का धूप, ज्वालाजी के पेड़े, दियोटसिद्ध के रोट और पूजा पद्धति से जुड़े बाजारों की क्षमता समझी जाए, तो धार्मिक स्थल औद्योगिक व सांस्कृतिक उत्पादन के रूप में विकसित हो सकते हैं।

कुछ | अलग

सपने बांटने वालों की जमात

यह कैसा कुत्तेगिरी का माहौल है भैय्या कि बहुत से धनी मानी लोगों को लगने लगा है कि वह अचानक गरीब हो गए हैं, और उनकी गरीबी का कोई अंत नहीं। दड़े-सट्टे की पर्चियां निकालने वाले क्रिप्टो करंसी के अलम्बरदार हो गए। अपना देश, डिजिटल हो रहा है न। लुडो और सांप और सीढ़ी के खेल, खेलों के जुआ संस्करण बन गए। हथेली पर सरसों जमाने वाले लोग उन्हें खेल रहे हैं। उसके सब्जबाग में सपनाजीवी लोगों को भटका लाखों के बारे-न्यारे कर रहे हैं, सुनो जी, इस बदलती दुनिया में साधु का वेष धारण किए लोग ऐसे-ऐसे चोरी ठगी के नए चोर दरवाजे निकालते हैं, कि हर पुराना तरीका पुरातनपंथी और नए की वार्निश ढूंढने लगता है। रंक से राजा, और राजा से रंक होने का पांसा पल्टू खेल यहां दिन-रात चलता है। आज जिसका पत्ता ऊपर था, कल वह फाडी हो गया और फाडी झंडाबरदारी कर रहे हैं। जी हां, जो कभी नैतिकता के अलम्बरदार थे, आज नैतिकता का ढोल कहां पीटें। ढोल पीटने वालों का तो कोहराम हो गया। और एक पाले से दूसरे पाले में कूदते लोग, आया राम गया राम को उपालम्भ नहीं ताकत मानने लगे। जमाना कयामत की चाल चल गया भैय्या। जो अपनी बात, अपने स्टैंड पर दृढ़ रहने की बात कहे, उसे कहते हैं, 'भैय्या इसे तो दीमक लग गया।' इसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, खुद कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार दिया। रंग बदल पल्टूराम हो जा। यही नए जमाने में जीने की सामझदारी है। प्रतिबद्धता और समर्पण रतौंधी है। उसे छोड़ विपक्ष में कूद उनकी गलबहियां ले। सवाल तो कुर्सी को सुशोभित करने का है।

दृष्टि | कोण

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से सुलगते सवाल और राजनीतिक निहितार्थ

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का संसद चलो आह्वान केवल एक विरोध मार्च नहीं, बल्कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की एक राजनीतिक रणनीति है। खासकर जिस तरह से इस आंदोलन को छात्र आंदोलन का स्वरूप दिलवाया जा चुका है, वह डीप स्टेट के इशारे पर बनी विपक्ष की शातिर सरकार घेरो रणनीति का कमाल भी करार दिया जा रहा है। देखा जाए तो संसद के मानसून सत्र के दौरान गत 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च करने के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे और कूच किया, वह बिल्कुल संगठित राजनीतिक आंदोलन के तर्ज पर हुआ। मजे की बात तो यह कि संसद के निकट पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो पूर्व प्रायोजित झड़प हुई और उसके बाद हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, इससे यह संसद मार्च राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन गया। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और अखबारों के दफ्तरों में इससे जुड़े कई नीतिगत सवालों पर भी बहस होने लगी। सोशल मीडिया पर जहां सरकार विरोधी भड़काऊ वीडियो वायरल होने लगे, वहीं सत्ताधारी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलनकारियों की कारगुजारियों के वीडियो साझा कर दिए, जिससे लोगों की सहानुभूति पुलिस और सरकार के साथ बनी रही। यदि संसद मार्च के घटनाक्रमों पर संतुलित नजर डालें तो यही प्रतीत होता है कि जब बड़ी संख्या में सीजेपी (CJP) समर्थक संसद चलो मार्च के लिए जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़े, तो भले ही उनकी मुख्य मांगें शिक्षा सुधार, परीक्षा-पत्र लीक और जवाबदेही था, लेकिन इरादे तोड़फोड़ वाले और खतरनाक थे, अन्यथा पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना पड़ता। चूंकि संसद के मानसून सत्र के दौरान माननीयों की सुरक्षा के दृष्टिगत दिल्ली पुलिस ने व्यापक बैरिकेडिंग की थी, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को रोका, हिरासत में लिया तथा कुछ स्थानों पर आंदोलनकारियों द्वारा उपद्रव करने के बाद आंसू गैस और बल प्रयोग की तस्वीरें सामने आईं। इससे अफरातफरी मच गई। देखा जाए तो

इस आंदोलन की प्रमुख मांगों में नीट (NEET) पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही, कुछ नेताओं द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ संवाद आदि हैं, लेकिन जो उत्पात दिखाई-सुनाई दिया, वह विपक्षी संस्कार नहीं तो क्या है? फिर भी, केंद्र सरकार ने आंदोलन के प्रतिनिधियों से बातचीत की पहल भी की, जो टकराव के बीच संवाद की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर CJP प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और मांगपत्र ग्रहण किया। बावजूद इसके आंदोलनकारी अपनी मांगों पर कायम हैं। सवाल है कि संसद मार्च के क्रम में जो कुछ गड़बड़ हुआ, क्या वह लोकतांत्रिक है, सही था या गलत? तो जवाब होगा कि युवाओं का शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा की निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाना लोकतंत्र का वैध हिस्सा है। वहीं, सरकार द्वारा आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप कदम है। फिर भी संसद मार्च के दौरान आंदोलनकारियों की ओर से कुछ कुछ गलत हुआ जो अनुचित लगा। यदि प्रदर्शनकारियों ने निषिद्ध क्षेत्र में जबरन प्रवेश करने या बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, तो वह कानून-व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं माना जाएगा। वहीं, यदि पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अनावश्यक कार्रवाई हुई, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय होनी चाहिए।

बम की झूठी धमकी देने वाला आरोपी गुजरात से गिरफ्तार दो दिन के पुलिस रिमांड पर

अजमेर (हिंस)। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और जिला एवं सत्र न्यायालय को ई-मेल के माध्यम से बम विस्फोट की झूठी धमकी देने के मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गुजरात से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को दो दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुजरात के सोमनाथ पाटन स्थित बेणेश्वर सोसायटी निवासी फलदू हार्दिक रमेशचंद के रूप में हुई है। पुलिस टीम उसे गुजरात से गिरफ्तार कर 21 जुलाई की देर रात अजमेर लाई थी। प्रारंभिक पूछताछ के बाद बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार 9 जुलाई को घूघरा स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को भेजे गए ई-मेल में कार्यालय परिसर को साइनाइड गैस और बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।

विपक्ष में बैठने से देश को गुमराह करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता : शेखावत

जोधपुर (हिंस)। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि विपक्ष में बैठने से तथ्यों को तोड़-मरोडडकर देश को गुमराह करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। विपक्ष के नेता को क्या यह सत्य नहीं पता है कि कांग्रेस ने ही पेपर लीक को समस्या को पनपाया और इसकी जड़ों को गहरा किया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के दौरान लगातार सामने आए पेपर लीक के प्रकरण इस विफलता की खुली गवाही हैं। सोशल मीडिया पर शेखावत ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती रहीं, जबकि मोदी सरकार ने शोर-शराबे के बजाय कार्रवाई का रास्ता चुना है। कड़े कानून बनाए, व्यवस्था को मजबूत किया और अब फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से दोषियों को शीघ्र और कठोर सजा सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया है। सवाल पूछने के लिए संसद से बड़ा कोई मंच नहीं है। सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने बहस से भागकर उपद्रव की राजनीति को चुना। भारत के भविष्य के साथ राजनीति करने वालों को यह याद रखना चाहिए कि युवाओं को कोरे नारे नहीं, निष्पक्ष परीक्षाएं और न्याय चाहिए।

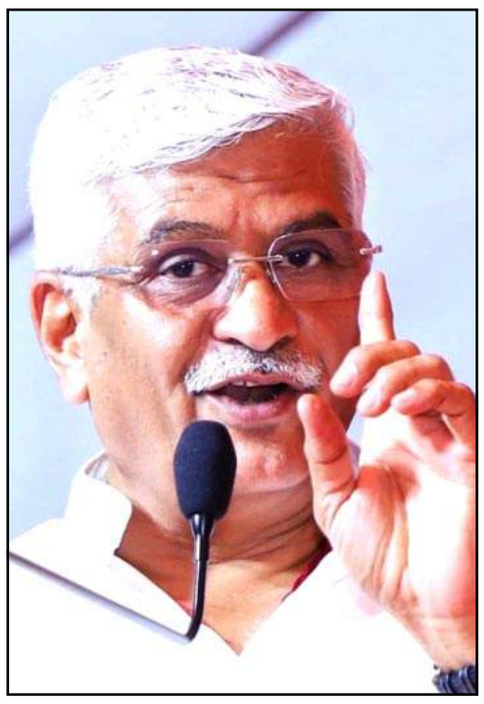

सरकार निकाय-पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार : गहलोत

जोधपुर (हिंस)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार निकाय और पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट संबंधी निर्देशों की पालना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया है, जो प्रदेशभर में सर्वे कर रहा है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा और उसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2026 के भीतर ही निकाय चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। यह बात उन्होंने जोधपुर प्रवास के दौरान कही। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किए चुनाव कराने की मांग कर रही है, जबकि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ओबीसी समाज को उसका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभागीय कार्यों की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रदेश के सबसे बड़े विभागों में शामिल है और इसका वार्षिक बजट करीब 20 हजार करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि विभाग अपने बजट का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, छात्रावास, आर्थिक सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करता है, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सकें। एनजीओ के संचालन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि विभाग से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। किसी भी संस्था को मान्यता देने से पहले उसकी ऑडिट रिपोर्ट और अन्य मानकों की जांच की जाती है। यदि किसी भी प्रकार की शिकायत सामने आती है, तो तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इससे पहले सर्किट हाउस पहुंचने पर नवपदस्थापित संयुक्त निदेशक बजरंग सारस्वत के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं, छात्रावासों और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आईडीएफसी बैंक घोटाले में सीबीआई ने चंडीगढ़ व लुधियाना में की छापेमारी

चंडीगढ़ (हिंस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीमों ने चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल) और चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अकाउंट से फंड के गलत इस्तेमाल के मामले में चंडीगढ़ और लुधियाना में कई जगहों पर जांच की है। सीबीआई प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि यह तलाशी पांच जगहों पर ली गई, जिनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फंड में धोखाधड़ी से फायदा उठाने वाले संदिग्ध लोगों के घर और बिजनेस की जगहें, सीएससीएल के सरकारी कर्मचारी अनुभव मिश्रा और जांच से जुड़ी प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं। तलाशी के दौरान कई अहम सबूत और सामान बरामद और जब्त किए गए। इनमें स्टोरेज ड्राइव, डिजिटल सिग्नेचर, प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जांच से जुड़े दूसरे कागजात जैसे डिजिटल सबूत शामिल हैं। जब्त किए गए कागजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच और एनालिसिस की जा रही है, जो जांच का हिस्सा है। राज्य सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने हरियाणा के स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो से जांच अपने हाथ में ली थी। आरोप है कि हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों के लगभग 657 करोड़ रुपए के सरकारी फंड को नकली/फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट और धोखाधड़ी वाले डेबिट ट्रांजेक्शन के जरिए निकाल लिया गया और बाद में शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया। अब तक, सीबीआई ने हरियाणा मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के तीन सरकारी कर्मचारी, दो कंपनियां और छह प्राइवेट व्यक्ति शामिल हैं। सीबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से जुड़े दो और मामले भी अपने हाथ में लिए हैं।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का केंद्र सरकार पर हमला

बोले, लोकतंत्र की अर्थी निकाल दी, पेपर लीक पर मांगा जवाब

अलवर (हिंस)। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार और राजस्थान की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र की भावना को कमजोर किया जा रहा है। जूली ने कहा कि छात्रों और युवाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वालों के साथ भी सख्ती की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भूख हड़ताल, पैदल मार्च और विपक्ष द्वारा सवाल पूछने तक पर कार्रवाई हो रही है। जूली ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा छात्रों के मुद्दे उठाए हैं और सरकार से जवाब मांगा है। जूली ने कहा कि गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने वालों को जिस तरह हटाया गया, उससे ऐसा लगा मानो लोकतंत्र की अर्थी निकाल दी गई हो। उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के उस बयान पर भी आपत्ति जताई, जिसमें प्रदर्शनकारियों को पत्थरबाज, विदेशी फंडिंग वाला और भाड़े का बताया गया था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देशभर में बड़ी संख्या में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं और युवाओं को वर्षों तक इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक रोकने के लिए सबसे सख्त कानून बनाया गया था, जिसमें 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया। वहीं केंद्र सरकार के कानून को उन्होंने अपेक्षाकृत कमजोर बताया। जूली ने कहा कि पेपर लीक और भर्ती में देरी के कारण कई युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। उनका कहना था कि युवाओं की मेहनत और समय बर्बाद होने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। जूली ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार होने के बावजूद युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन करने पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेस छात्रों के समर्थन में उनके साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया और छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार को जवाब देना चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

पेपर लीक के दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा : गौरव गौतम

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों के दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया है।गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में गौरव गौतम ने कहा कि राहुल गांधी सदन में नीट पर चर्चा करने की बजाए भाग क्यों रहे हैं। राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर समाधान खोजने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नीट और पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर संसद में विस्तृत चर्चा चाहती है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी चर्चा करने की बजाए देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं जो शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष के पास कोई सकारात्मक सुझाव हैं तो सरकार उनका भी स्वागत करेगी। खेल मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी सदन में चर्चा करने के बजाय देश में भ्रम और अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ लेना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं को बहला-फुसलाकर उन्हें भड़काने का प्रयास कर रही है, जबकि छात्रों के भविष्य जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गौरव गौतम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शिक्षा का बजट लगभग 8,225 करोड़ रुपए था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ाकर लगभग 1.49 लाख करोड़ रुपए किया गया। उन्होंने कहा कि देशभर में एम्स, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। कॉमनवेल्थ खेलों को लेकर पूछे गए सवाल पर गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा देश का खेल पावर हाउस है।

मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक का अनशन 26वें दिन भी जारी, हालत स्थिर

गुरुग्राम (हिंस)। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद अनशन गुरुवार को 26वें दिन भी जारी रहा। अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनकी स्थिति स्थिर है और सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मानक सामान्य हैं।गुरुवार शाम को अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर डॉ. संजय दुरानी की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि सोनम की स्वास्थ्य स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। वह स्टेबल और अलर्ट हैं। पूरी तरह से होश में हैं। उनके सभी वाइटल पैरामीटर सामान्य सीमा में हैं। वांगचुक का इलाज उनकी सूचित सहमति के अनुसार जारी है। उल्लेखनीय है कि सोनम वांगचुक को 21 जुलाई की शाम हाईकोर्ट के आदेश पर मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था।

आनासागर के मुद्दे पर अजमेर बंद, कांग्रेस का प्रदर्शन और भाजपा का श्रमदान

अजमेर (हिंस)। ऐतिहासिक आनासागर झील के संरक्षण, मूल स्वरूप की पुनर्स्थापना और पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर गुरुवार को कांग्रेस के आह्वान पर अजमेर बंद रहा। शहर के कई प्रमुख बाजार बंद रहे, जबकि भाजपा ने लगातार दूसरे दिन आनासागर झील पर श्रमदान और सफाई अभियान चलाकर कांग्रेस के आंदोलन का जवाब दिया। झील संरक्षण के मुद्दे पर दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज रहा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व विधायक डॉ. श्रीगोपाल बाहेती, रामचंद्र चौधरी, महेंद्र सिंह रलावता, द्रोपदी कोली, राजेश टंडन सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर व्यापारियों और आमजन से बंद का समर्थन करने की अपील की। कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को फूल भेंट कर सहयोग का अनुरोध किया। कुछ स्थानों पर बैंक बंद कराने, रिक्शों से यात्रियों को उतरने का आग्रह करने तथा पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन की घटनाएं भी सामने आईं। कांग्रेस का आरोप है कि आनासागर झील में मछलियों की मौत, बढ़ते प्रदूषण और दुर्गंध से शहरवासियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है तथा झील संरक्षण के नाम पर केवल प्रतीकात्मक गतिविधियां की जा रही हैं। डॉ. राजकुमार जयपाल ने कहा कि यह जनता का आंदोलन है और शहर के जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। शहर कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश गुप्ता ने बताया कि बंद से अस्पताल, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को मुक्त रखा गया। बंद को विभिन्न व्यापारिक, सामाजिक और परिवहन संगठनों का समर्थन मिला। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं भाजपा ने लगातार दूसरे दिन भी आनासागर झील पर श्रमदान और सफाई अभियान चलाया। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि झील की वर्तमान स्थिति के लिए कांग्रेस स्वयं जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने झील में गिरने वाले गंदे नालों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के दौरान आनासागर एस्केप चैनल के लिए प्रस्तावित राशि का अन्य कार्यों में उपयोग किया गया। रमेश सोनी ने दावा किया कि भाजपा सरकार बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के प्रयासों से झील की डी-सिल्टिंग का कार्य स्वीकृत हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इसमें कानूनी बाधाएं उत्पन्न कीं। उन्होंने कहा कि डी-सिल्टिंग से झील की जलधारण क्षमता बढ़ेगी, जलकुंभी की समस्या कम होगी और जल की गुणवत्ता में सुधार होगा।

लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर अराजक राजनीति कर रही है कांग्रेस : राजीव रंजन साह

सहरसा (हिंस)। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव रंजन साह ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक परंपराओं एवं संवैधानिक मर्यादाओं के प्रतिकूल है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन विरोध भी संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जब दिल्ली एवं पटना में छात्रों के नाम पर आंदोलन चल रहे हैं, तब कुछ विपक्षी दल छात्रों की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय उनके आंदोलन को राजनीतिक मंच बनाकर राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। छात्रों की भावनाओं का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है।भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजीव रंजन साह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने संदेश के माध्यम से छात्रों के हितों एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। भाजपा सदैव युवाओं और छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है तथा छात्र हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि यदि किसी परीक्षा या व्यवस्था में कोई कमी है तो उसका समाधान संवाद, पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए,न कि अराजकता फैलाकर,भ्रम पैदा कर और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अनावश्यक दबाव बनाकर। राजीव रंजन साह ने कहा कि भाजपा राष्ट्रहित, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध है। जनता सब देख रही है और छात्र हित के नाम पर की जा रही अवसरवादी राजनीति तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के उल्लंघन का समय आने पर लोकतांत्रिक तरीके से उचित जवाब देगी। लोकतंत्र का सम्मान, राष्ट्रहित और युवाओं का उज्ज्वल भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है तथा इनके विरुद्ध होने वाली किसी भी प्रकार की राजनीति का भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती रहेगी।

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

पटना (हिंस)। बिहार में भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस अरुण कुमार झा ने दिया। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, वायरलेस लॉगबुक, मोबाइल फोन का डाटा सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 28 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता आशा देवी के अधिवक्ता अमित कुमार ने कोर्ट से 17 जून को हुए एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और तय समय सीमा के भीतर कानून के तहत जांच करने मांग की। साथ ही घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, वायरलेस लॉगबुक, स्टेशन डायरी इंट्री, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बॉडी कैमरा फुटेज, सीजर रिकॉर्ड, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को सुरक्षित करने की गुहार लगाई है। अधिवक्ता ने कोर्ट से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंकवेस्ट रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट की प्रति आवेदिका को देने साथ में मृतक का मोबाइल फोन और उसके पास से जब्त सभी सामान वापस देने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने बताया कि 16/ 17 जून की रात बिना बताए याचिकाकर्ता के घर में बगैर महिला सिपाही के प्रवेश किया, जिसकी जांच करने की मांग की। इसके अलावा 17 जून को आशा देवी के पति काशीनाथ तिवारी को शाहपुर थाना में रखा गया। उल्लेखनीय है कि, भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस ने मुठभेड़ के नाम पर युवक भरत भूषण तिवारी को गोली मार दी थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि भरत ने जब हथियार फेंक दिया, तब पुलिस ने उसे गोली मारी। हालांकि, इस मामले में आयोग की तरफ से न्यायिक जांच चल रही है।

अंधकार, अराजकता और अज्ञानता से मुक्ति का माध्यम है भक्तिसम्मत ज्ञान : सीएम योगी

गोरखपुर (हिंस)। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन में भक्ति के बिना अंधकार, अराजकता व अज्ञानता होती है। जीवन सुगमता को जानने के लिए हमें ज्ञान और भक्ति का अनुगामी बनना पड़ेगा। यह ज्ञान और भक्ति हमें श्रीराम कथा और श्रीमद्भावगत कथा जैसी पावन कथाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरुवार से आयोजित सप्तदिवसीय श्रीराम कथा के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में व्यासपीठ का पूजन करने के बाद उन्होंने कहा कि जीवन में जहां भक्ति नहीं है, वहां अंधकार ही अंधकार है। भक्ति के बिना जीवन में अराजकता ही अराजकता और अज्ञानता ही अज्ञानता है। अंधकार, अराजकता और अज्ञानता से मुक्ति पाने का माध्यम भक्तिसम्मत ज्ञान ही है। गोरक्षपीठाधीश्वर ने श्रीराम कथा की महत्ता को समझाते हुए कहा कि सनातन धर्म की परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का नाम ऐसा है जो हर भारतीय के मन और अंत:करण में पूरी श्रद्धा एवं पूरी भक्ति से जुड़ा है। हर सनातनी के श्वांस-श्वांस में प्रभु श्रीराम बसते हैं। भगवान श्रीराम का नाम ऐसा है जिससे जीवन में चाहे कोई बाल हो या वृद्ध, अधेड़ हो या जवान, गृहस्थ हो या विरक्त, हर कोई इस नाम को अपने नजदीक पाता है। सीएम योगी ने कहा कि देश के अंदर हम कहीं भी जाते हैं, चाहे कोई हिंदीभाषी हो अहिंदीभाषी, सबकी तरफ से अभिवादन का एक ही स्वर होता है- जय श्रीराम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में आपसी अभिवादन के लिए एक ही शब्द सुनाई देता है- राम राम जी। उन्होंने कहा कि जय श्रीराम या राम राम जी का यह संबोधन हमारे सनातन संस्कार का संबोधन है। इस संबोधन ने हमारे संस्कार को तो जोड़ा ही, जीवन की हर परिस्थिति में मर्यादा की लक्ष्मणरेखा भी खींची। सीएम योगी ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अपने पावन धाम और तीर्थस्थलों से यह देश की हृदयस्थली के रूप में प्रतिष्ठित है। जीवन के किसी भी पक्ष में जब मर्यादा की बात होती है तो सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम और अयोध्या की ओर देखते हैं। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए व्यक्ति अविनाशी काशी को देखता है। जीवन में भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए लोग मथुरा-वृंदावन को देखते हैं। समरसता क्या होनी चाहिए, इसके दर्शन प्रयागराज में होते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया चाहें जितना दुष्प्रचार कर ले, सनातन मूल्यों को जानने का अवसर उत्तर प्रदेश के तीर्थों में ही प्राप्त होता है। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के उपरांत श्रद्धालुओं को श्रीराम कथा का रसपान व्यासपीठ पर विराजमान कथा व्यास, प्रयागराज से पधारे आचार्य शांतनु जी महाराज ने कराया। यह कथा प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे तक सुनाई जाएगी। श्रीराम कथा के शुभारंभ से पूर्व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मुख्य मंदिर से कथा स्थल तक बैंडबाजे, शंख ध्वनि की गूंज तथा 151 वेदपाठी विद्यार्थियों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीरामचरितमानस की पोथी शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा के कथा स्थल पहुंचने पर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ व यजमानगण ने व्यासपीठ की पूजा की। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, हनुमानगढ़ी अयोध्या के आए महंत राजूदास, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, यजमान बैजनाथ जायसवाल, अमित जायसवाल, कई साधु-संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

प्राइमरी मार्केट में एक्सट्रानेट टेक का आईपीओ लान्च, 27 जुलाई तक लगा सकते हैं बोली

नई दिल्ली

मध्य प्रदेश की आईटी साल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी एक्सट्रानेट टेक्नोलाजीज का 166.80 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 27 जुलाई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 28 जुलाई को शेयरों का अलाटमेंट किया जाएगा, जबकि 29 जुलाई को अलाटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 30 जुलाई को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। पहले दिन दोपहर 2:30 बजे तक ये आईपीओ 61 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ था।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 120 रुपये से लेकर 127 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 110 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम 1 लाट यानी 110 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 13,970 रुपये का निवेश करना होगा। इसी तरह रिटेल इनवेस्टर 1,95,580 रुपये के निवेश से अधिकतम 14 लाट में 1,540 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 1,31,34,000 करोड़ नए शेयर बेचे जा रहे हैं।

इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 36.96 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 48.04 प्रतिशत हिस्सा और नान इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इस इश्यू के लिए शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि केफिन टेक्नोलाजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है।

एक्सट्रानेट टेक्नोलाजीज की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है।

न्यूज ब्रीफ

आईटीसी का 2035 तक आठ लाख करोड़ रुपये के एफएमसीजी बाजार का लक्ष्य

नई दिल्ली। देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनी आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजीव पुरी ने गुरुवार को कहा कि कंपनी ने 2035 तक अपने पैकेज्ड गुड्स व्यवसाय के लिए 8 लाख करोड़ रुपये के एड्रेसेबल मार्केट (कुल संभावित बाजार) का लक्ष्य रखा है। कंपनी ब्रांड निर्माण, डिजिटल वाणिज्य के विस्तार और रणनीतिक अधिग्रहणों के जरिये अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। आईटीसी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि भारतीय एफएमसीजी बाजार उल्लेखनीय विस्तार के लिए तैयार है, देश का उपभोक्ता परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। उन्होंने बताया कि कंपनी इस विशाल अवसर को भुनाने के लिए ब्रांड-बिल्डिंग, एआई-संचालित उपभोक्ता अंतर्दृष्टि, डिजिटल कामर्स और रणनीतिक अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पुरी ने कहा कि आकांक्षी भारत का उदय, प्रीमीयमीकरण, जेन-जेड और जेन-अल्फा उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या, डिजिटल पहुंच का विस्तार और त्वरित वाणिज्य (क्विक कामर्स) का बढ़ता चलन उत्पाद श्रेणियों, वितरण माध्यमों और उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन रुझानों का लाभ उठाने के लिए आईटीसी कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित उपभोक्ता अंतर्दृष्टि प्रणाली का उपयोग कर रही है, जिससे सूक्ष्म स्तर पर उपभोक्ताओं का वर्गीकरण संभव हो रहा है और उनकी बदलती जरूरतों, जीवनशैली तथा उपभोग के अवसरों के अनुरूप अलग-अलग उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं।

विदेशी बैंकों ने ब्याज दर कटौती का सर्वाधिक लाभ ग्राहकों तक पहुंचाया: आरबीआई

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नीतिगत दरों में कटौती का सबसे अधिक फायदा ग्राहकों को विदेशी बैंकों ने पहुंचाया है। आरबीआई के मासिक बुलेटिन के जारी होने के बाद यह जानकारी सामने आई कि विदेशी बैंकों ने मौजूदा ब्याज दर कटौती चक्र के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में ऋण और जमा, दोनों पर ब्याज दरों में अधिक कमी की। आरबीआई के अनुसार विदेशी बैंकों ने मौद्रिक नीति में नरमी के दौर में ग्राहकों तक राहत पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। रुपए में लिए गए नए कर्ज पर भारित औसत ब्याज दर में विदेशी बैंकों ने 1.24 प्रतिशत की प्रभावशाली कटौती की, जबकि निजी बैंकों ने 1.08 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने केवल 0.66 प्रतिशत अंक की कमी की।

इंडिगो एयरलाइन को पहली तिमाही में 238 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की (अप्रैल-जून) पहली तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया है। कंपनी को अप्रैल-जून तिमाही में 238 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ है। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 2,176.3 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 25,614.1 करोड़ रुपये हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 21,542.6 करोड़ रुपये थी। इस दौरान कंपनी के कुल खर्च में भी वृद्धि हुई है। इंडिगो ने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव तथा पश्चिम एशिया में संकट का तिमाही की लाभप्रदता पर संयुक्त असर पड़ा, जिससे कंपनी को 2.4 अरब रुपये (238 करोड़ रुपये) का शुद्ध घाटा हुआ है। कंपनी के मुताबिक ईंधन की ऊंची कीमतों, विदेशी मुद्रा विनिमय में नुकसान और पश्चिम एशिया में जारी संकट का भी लाभ पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो की मूल कंपनी है। घरेलू विमानन बाजार में इंडिगो की हिस्सेदारी 66 फीसदी से अधिक है। इंडिगो के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में परिचालन माहौल चुनौतीपूर्ण रहा। ईंधन की ऊंची लागत और पश्चिम एशिया में नेटवर्क संबंधी बाधाओं का कंपनी की लाभप्रदता पर असर पड़ा। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मांग मजबूत बनी रही और बेहतर प्रतिफल तथा ग्राहकों की लगातार बढ़ती पसंद के कारण हमारी आय में सालाना आधार पर वृद्धि हुई। इस दौरान हमने 3.1 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवाएं प्रदान कीं। भाटिया ने बताया कि ईंधन लागत में वृद्धि और रुपये में गिरावट के कारण पहली तिमाही में कंपनी को लगभग 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ा है।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला इंडो एमआईएम का आईपीओ, 30 जुलाई को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली

प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी इंडो एमआईएम का 3,811.21 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 27 जुलाई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 28 जुलाई को शेयरों का अलाटमेंट किया जाएगा, जबकि 29 जुलाई को अलाटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 30 जुलाई को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। पहले दिन दोपहर 3:15 बजे तक ये आईपीओ 82 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ था।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 461 रुपये से लेकर 485 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 30 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम एक लाट यानी 30 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 14,550 रुपये का निवेश करना होगा। इसी तरह रिटेल इनवेस्टर 1,89,150 रुपये के निवेश से अधिकतम 13 लाट में 390 शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ के तहत 1 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 7,86,00,300 शेयर जारी हो रहे हैं। इनमें 1,03,09,278 नए शेयर जारी हो रहे हैं, जबकि 6,82,91,022 शेयर आफर फार सेल विंडो के जरिये जारी किए जा रहे हैं।

इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 49.87 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 34.91 प्रतिशत हिस्सा और नान इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 14.96 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा कंपनी के एंप्लायीज के लिए 0.26 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि केफिन टेक्नोलाजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है।

इंडो एमआईएम की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 283.73 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में उछल कर 423.73 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 533.54 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 2,900.38 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 3,373.97 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 4,320.70 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज के बोझ में उतार चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी पर 1,085.01 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 1,247.20 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ घट कर 1,090.49 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया था।

इस अवधि में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस लगातार बढ़ता गया। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 1,889.04 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 2,030.81 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो इस दौरान कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 2,573.46 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया था।

इस अवधि में कंपनी के नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 2,050.51 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 2,199.43 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में ये 2,819.55 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह ईबीआईटीडीए (अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्सेज, डिप्रेशिएशंस एंड एमार्टाइजेशन) 2023-24 में 743.46 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 932.60 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का ईबीआईटीडीए 1,070.92 करोड़ रुपये के स्तर पर था।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला लोहिया कार्प का आईपीओ, 30 जुलाई को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली

टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मशीनरी और सहायक उपकरण बनाने वाली कंपनी लोहिया कार्प का 1,102.08 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 27 जुलाई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 28 जुलाई को शेयरों का अलाटमेंट किया जाएगा, जबकि 29 जुलाई को अलाटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 30 जुलाई को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। पहले दिन दोपहर दो बजे तक ये आईपीओ 18 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ है।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 404 रुपये से लेकर 425 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 35 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम एक लाट यानी 35 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 14,875 रुपये का निवेश करना होगा। इसी तरह रिटेल इनवेस्टर 1,93,375 रुपये के निवेश से अधिकतम 13 लाट में 455 शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ के तहत 1 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 2,59,31,407 शेयर आफर फार सेल विंडो के जरिये बेचे जाएंगे।

इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा और नान इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इस इश्यू के लिए इक्वीरस कैपिटल लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है। वहीं एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी को 117.84 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़ कर 193.45 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2024-25 में इसे 1,386.47 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़ कर 1,737.87 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

अमेरिका-ईरान तनाव से कच्चा तेल 98 डालर प्रति बैरल के पार

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एकबार फिर तेजी दर्ज हुई है। ब्रेंट क्रूड गुरुवार को 4 फीसदी बढ़कर 98 डालर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जो पिछले छह हफ्तों का उच्चतम स्तर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबार के दौरान कच्चे तेल (क्रूड आयल) की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड 4.58 डालर यानी 4.87 फीसदी की तेजी के साथ 98.65 डालर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जो पिछले 6 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई क्रूड) भी 3.69 डालर यानी 4.25 फीसदी की उछाल के साथ 90.52 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने देश में महंगाई और ऊर्जा संकट बढ़ा दिया है। इससे भारतीय मुद्रा रुपये और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के फ्लो पर असर पड़ने की संभावना है। वहीं, कच्चे तेल के महंगे होने से भारत की आयल मार्केटिंग कंपनियों के रिटेल पयूल मार्जिन पर भारी दबाव पड़ा है, जिससे डीजल पर कंपनियों को प्रति लीटर 20.4 रुपये का घाटा हो रहा है।

सर्राफा बाजार में चमका सोना, चांदी का भी बढ़ा भाव

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। भाव में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 2,100 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 2,190 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। वहीं चांदी के भाव में भी 5,200 रुपये प्रति किलोग्राम की जोरदार तेजी नजर आ रही है।

भाव में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,46,420 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,46,570 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,34,310 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,34,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,40,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,46,570 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,460 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,46,420 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,34,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,46,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,360 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,46,420 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,34,310 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,46,420 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,34,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,470 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,34,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,46,570 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,34,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,470 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,34,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,46,570 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,34,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,46,420 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 1,34,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान कमजोरी के साथ बंद हुए। डाउ जान्स फ्यूचर्स भी फिलहाल गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान तेजी का रुख बना रहा। वहीं एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार दबाव बना रहा, जिसकी वजह से वाल स्ट्रीट के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए।

एस एंड पी 500 इंडेक्स 0.14 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 7,498.96 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 146.30 अंक यानी 0.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,690.90 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। डाउ जान्स फ्यूचर्स भी फिलहाल 0.08 प्रतिशत टूट कर 52,175.30 अंक के स्तर पर आ गया है।

अमेरिकी बाजार के विपरीत यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान उत्साह का माहौल बना रहा। एफटीएसई इंडेक्स 131.06 अंक यानी 1.22 प्रतिशत की मजबूती के साथ 10,716.97 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.89 प्रतिशत की तेजी के साथ 8,437.89 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 144.06 अंक यानी 0.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,155.41 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के नौ बाजार में से पांच के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि चार सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी 0.31 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,887.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.58 प्रतिशत लुढ़क कर 5,562.72 अंक के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा ताईवान वेटेड इंडेक्स 312.31 अंक यानी 0.70 प्रतिशत टूट कर 44,513.47 अंक के स्तर पर और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.19 प्रतिशत फिसल कर 3,859.69 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

दूसरी ओर, निक्केई इंडेक्स 194.40 अंक यानी 0.29 प्रतिशत की तेजी के साथ 66,310 अंक के स्तर पर आ गया है। इसी तरह सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,642.02 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। कोस्पी इंडेक्स ने जोरदार छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 199.92 अंक यानी 2.94 प्रतिशत उछल कर 6,997.62 अंक के स्तर पर आ गया है। इसी तरह हैंग सेंग इंडेक्स 353.34 अंक यानी 1.40 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,246 अंक के स्तर पर और जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 1.28 प्रतिशत कि बढ़त के साथ 6,415.79 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

चार महिला जूडो खिलाड़ियों ने कामनवेल्थ गेम्स में बनाई जगह, मजबूत प्रशिक्षण व्यवस्था का दिखा असर

नई दिल्ली

भारतीय जूडो को लंबे समय से जिस मजबूत खिलाड़ी विकास प्रणाली की जरूरत थी, उसका असर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगा है। बेहतर प्रशिक्षण, वैज्ञानिक तैयारी और निरंतर सहयोग के दम पर चार भारतीय महिला जूडो खिलाड़ियों ने ग्लास्गो कामनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में स्थान हासिल किया है।

कामनवेल्थ गेम्स के लिए चुनी गई खिलाड़ियों में मध्य प्रदेश की यामिनी मौर्या, उत्तराखंड की उन्नति शर्मा, पंजाब की इशरूप नारंग और मणिपुर की तखेलंबम इनुंगनबी शामिल हैं। चारों खिलाड़ियों ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह पक्की की है।

इन खिलाड़ियों को एक्सिस बैंक और इंस्पायर इंस्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स (आईआईएस) के संयुक्त खिलाड़ी विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं मिलती रही हैं। इस पहल के माध्यम से अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को सहायता दी जा चुकी है, जिनमें 471 जूनियर और 53 एलीट महिला जूडो खिलाड़ी शामिल हैं।

इस कार्यक्रम से जुड़े खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 140 से अधिक पदक जीते हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों को जापान, जार्जिया और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में आयोजित 11 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में हिस्सा लेने का अवसर मिला, जिससे उन्हें विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव प्राप्त हुआ।

एक्सिस बैंक के ग्रुप हेड विजय मुलबगल ने कहा कि खिलाड़ियों को सही माहौल और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने से उनके प्रदर्शन में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है और कामनवेल्थ गेम्स के लिए चार खिलाड़ियों का चयन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

वहीं, आईआईएस की अध्यक्ष मनीषा मल्होत्रा ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य खिलाड़ियों को केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना है। भारतीय जूडो में हाल के वर्षों में उभरती नई प्रतिभाओं, विशेषकर पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के खिलाड़ियों की बढ़ती मौजूदगी यह संकेत देती है कि देश में खेल का आधार लगातार मजबूत हो रहा है। अब नजर इस बात पर होगी कि ये खिलाड़ी कामनवेल्थ गेम्स में अपने प्रदर्शन से भारत के पदक अभियान को कितना आगे ले जा पाती हैं।

न्यूज ब्रीफ

चाइना ओपन 2026: अंतिम-16 में हारकर बाहर हुईं पी.वी. सिंधु

चांगझोउ। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु का चाइना ओपन 2026 में सफर अंतिम-16 दौर में ही समाप्त हो गया। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में मेजबान चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चेन यू फेई ने शानदार वापसी करते हुए सिंधु को 16-21, 22-20, 21-18 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सिंधु ने मुकाबले की शानदार शुरुआत करते हुए पहला गेम अपने नाम किया। हालांकि दूसरे गेम में उनके पास मैच खत्म करने के चार मौके थे, लेकिन वह उनका फायदा नहीं उठा सकीं और चेन ने लगातार पांच अंक जीतकर मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। पहले गेम में चेन ने 12-6 की बढ़त बना ली थी, लेकिन सिंधु ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 16-16 से बराबर किया और इसके बाद लगातार अंक जुटाकर 21-16 से गेम जीत लिया। दूसरे गेम में सिंधु पूरी तरह नियंत्रण में नजर आई और 20-17 की बढ़त के साथ उनके पास चार मैच प्वाइंट थे। लेकिन इसी मोड़ पर चेन ने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार पांच अंक हासिल किए और 22-20 से गेम जीतकर मुकाबले को तीसरे गेम में पहुंचा दिया।

भारत की अनाहत विश्व जूनियर स्क्वैश के क्वार्टर फाइनल में पहुंची

ओंटारियो। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह कनाडा में जारी विश्व जूनियर स्क्वैश के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गयी हैं। अनाहत ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की डायस ये सैन ली को सीधे गेम में आसानी से हरा दिया। इसी के साथ ही अनाहत लगातार दूसरे साल इस अहम टूर्नामेंट में पदक की दौड़ में बनी हुई है। अनाहत ने मुकाबले में 11-4, 11-8 और 11-3 से जीत हासिल की। इस खिलाड़ी ने पिछले साल इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। अब अंतिम आठ के मुकाबले में अनाहत का सामना मिस्र की हबीबा रिजक से होगा। वहीं हबीबा ने ने एक अन्य प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका की शार्लेट जे को हराया था। वहीं महिला वर्ग के अन्य मुकाबलों की बात करें तो बेल्जियम की सवाना मोक्सहैम ने शानदार वापसी करते हुए हांगकांग की एना क्वांग को 3-1 से जबकि । मिस्र की मलिका एलकारावसी ने अमेरिका की दिया यादव को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।, हांगकांग की हेलेन टैंग ने मलेशिया की हार्लीन टैन को हराया। दूसरी ओर पुरुष वर्ग में भी शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों ने अपनी जीत क सिलसिला जारी रखा। शीर्ष वरीयता प्राप्त मोहम्मद जकारिया ने पाकिस्तान के नौमान खान को आसानी से हराकर अगले दौर में जगह बनायी। एक अन्य मुकाबले में फ्रांस के अमीर खालिद-जौसेलिन ने इंग्लैंड के रानी हिकलिंग को सीधे गेम में हराया। पुरुष वर्ग में हालांकि भारत के आर्यवीर दीवान को अमेरिका के यासीन शलाबी ने आसानी से 11-4, 11-1 और 11-5 हरा दिया।

कुलदीप अब काउंटी क्रिकेट टीम योर्कशायर से खेलेंगे

नई दिल्ली। भारतीय टीम से बाहर चल रहे स्पिनर कुलदीप यादव अब इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में

यार्कशायर टीम की ओर से खेलते हुए दिखेंगे। कुलदीप के इंग्लैंड दौरे के एक भी मैच में जगह नहीं मिली थी। वहीं इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी शामिल नहीं किया गया था। इसी कारण उन्होंने काउंटी की ओर रुख किया है जिससे वहां अच्छा प्रदर्शन कर टीम में वापसी की दावेदारी करें। क्लब के साथ किये करार के तहत वह मौजूदा सत्र में आठ गेम ही खेलेंगे। इस करार के तहत ही कुलदीप अब यार्कशायर से जुड़ने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं यार्कशायर के अनुसार कुलदीप पांच मेट्रो बैंक वन डे कप मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद वे सितंबर में होने वाले चार रोथेसे काउंटी चैम्पियनशिप फिक्स्चर में से तीन के लिए हेडिंग्ले लौटेंगे। वह शुक्रवार को ग्लैमर्गिन के खिलाफ नेथ में होने वाले 50 ओवर के मैच के लिए सीधे टीम में शामिल होंगे। वहीं यार्कशायर में शामिल होने से उत्साहित कुलदीप ने कहा, मैं यार्कशायर जैसे क्लब की ओर से खेलने का अवसर मिलने से उत्साहित हूं। उन्होंने आगे कहा, मैंने हमेशा यहां के हालातों में खेलने का आनंद लिया है, और प्रबंधन से बात करने के बाद, मैं टीम में शामिल होने को लेकर उत्साहित हूं।

ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल खेलों की 10 स्पर्धाओं में उतरेंगे 3000 खिलाड़ी, भारतीय दल की कमान संभालेंगे नीरज

ग्लास्गो

स्काटलैंड के ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल का अब तक का सबसे छोटा संस्करण शुरू होने जा रहा है। ये पिछले तीन दशकों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतने कम खेलों को रखा गया है। इसका कारण बजट की कमी है। इस बार केवल 10 खेल स्पर्धाएं रखी गयी हैं जिसमें 74 देशों के करीब 3000 खिलाड़ी उतर रहे हैं।

ग्लास्गो ओवो हाइड्रो स्टेडियम में गुरुवार को उद्घाटन समारोह के साथ इन खेलों की औपचारिक शुरुआत होगी। ग्लास्गो दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी संभाली है। इससे पहले साल 2014 में भी यहां खेल हुए थे। इस आयोजन का बजट करीब 160 मिलियन पाउंड है, जो बर्मिंघम 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों से 60 फीसदी कम है। इस बार कम खेल स्पर्धाएं रखे जाने का विपरीत प्रभाव भारत पर पड़ेगा है। भारत मैनचेस्टर 2002 से हर राष्ट्रमंडल खेलों में शीर्ष पांच में रहा है पर इस बार हाकी, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और निशानेबाजी जैसे महत्वपूर्ण खेलों को शामिल नहीं किया गया है। जिससे भारत को नुकसान होगा क्योंकि पिछली इन खेलों में ही उसे अधिक पदक मिले थे। अब भारत की उम्मीदें एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन जैसे प्रमुख खेलों पर पर रहेंगी। एथलेटिक्स में भारत ने 32 सदस्यीय मजबूत दल उतारा है, ये 22 पदक स्पर्धाओं में भाग लेगा। इस दल की कमान दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा करेंगे। वहीं ऊंची कूद में सर्वेश कुशारे, लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर, त्रिकूद में प्रवीण चित्रावेल और महिला तथा पुरुष चार गुणा 400 मीटर रिले टीमों से भी भारत को पदक की उम्मीदें रहेंगी। पिछले बर्मिंघम खेलों में एथलेटिक्स से भारत ने आठ पदक जीते थे। वहीं भारोत्तोलन में ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू पर सबकी नजरें रहेंगी। मीराबाई ने पिछले दो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं और इस बार भी उनसे पदक की प्रबल उम्मीद है। वहीं मुक्केबाजी में, टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन (75 किलो वर्ग) राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला पदक जीतने का प्रयास करेंगीगी। 57 किलो वर्ग में विश्व चैंपियन जैसमीन लंबोरिया स्वर्ण के लिए उतरेंगी। एशियाई चैंपियन प्रीति पवार (54 किलो), साक्षी चौधरी (51 किलो) और अरुंधती चौधरी (70 किलो) भी मजबूत दावेदार हैं। दूसरी ओर पुरुष वर्ग में, नरेंदर बेरवाल (90 किलो) और विश्व कप पदक विजेता सचिन सिवाच (60 किलो) से भी पदक की उम्मीदें हैं। इन प्रमुख खेलों के अलावा, भारत को लान बाल और जूडो से भी उम्मीदें हैं। लान बाल में भारत ने बर्मिंघम में महिला वर्ग में स्वर्ण और पुरुष वर्ग में रजत पदक जीते थे, जिसे वे इस बार दोहराना चाहेंगे। जूडो में भी पिछले खेलों के तीन पदकों से बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य है। इस बार छह खेलों में पैरा स्पर्धाएं भी साथ में हो रही हैं, जिससे पैरा एथलीटों से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।

फीफा विश्व कप-2026 की ड्रीम इलेवन घोषित, मेसी, एम्बाप्पे और हालैंड को मिली जगह

ज्यूरिख

फीफा विश्व कप 2026 की प्रशंसकों द्वारा चुनी गई ड्रीम इलेवन की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे, नार्वे के एरलिंग हालैंड और इंग्लैंड के जूद बेलिंघम जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को जगह मिली है। विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित करने वाले केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा को भी ड्रीम इलेवन में शामिल किया गया है। 40 वर्षीय वोजिन्हा को गोलकीपर के लिए हुए प्रशंसकों के मतदान में 39.6 प्रतिशत वोट मिले। उन्होंने विश्व कप में पदार्पण करने वाले केप वर्डे के लिए शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि, टूर्नामेंट का गोल्डन ग्लव पुरस्कार स्पेन के उनाई सिमोन को मिला था, जिसका चयन फीफा के तकनीकी समूह ने किया था। विश्व कप से पहले पुर्तगाल के दूसरे डिवीजन क्लब चावेस छोड़ने के बाद वोजिन्हा किसी क्लब से नहीं जुड़े थे। इसके बावजूद उन्होंने विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्पेन के खिलाफ गोलरहित ड्रा में सात शानदार बचाव किए। इसके अलावा उन्होंने अंतिम-32 मुकाबले में अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय तक खेलने के लिए मजबूर करने में भी अहम भूमिका निभाई।

नार्वे के स्टार स्ट्राइकर एरलिंग हालैंड को फारवर्ड खिलाड़ियों के मतदान में 27.5 प्रतिशत वोट मिले। हालैंड ने पांच मैचों में सात गोल दागे और अपनी टीम को पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल में पांच बार की चैंपियन ब्राजील के खिलाफ 2-1 की जीत में दो गोल किए थे। नार्वे का सफर इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ समाप्त हुआ। ड्रीम इलेवन में हालैंड और वोजिन्हा के अलावा लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे, जूद बेलिंघम, रोद्री, माइकल ओलिसे, पेड्रो पोरो, लिसांड्रो मार्टिनेज, दायो उपामेकानो और मार्क कुकुरेला को भी स्थान मिला है। फीफा विश्व कप 2026 ड्रीम इलेवन

गोलकीपर: वोजिन्हा (केप वर्डे)

डिफेंडर: पेड्रो पोरो (स्पेन), लिसांड्रो मार्टिनेज (अर्जेंटीना), दायो उपामेकानो (फ्रांस), मार्क कुकुरेला (स्पेन)

मिडफील्डर: रोद्री (स्पेन), माइकल ओलिसे (फ्रांस), जूद बेलिंघम (इंग्लैंड)

फारवर्ड: लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना), एरलिंग हालैंड (नार्वे), किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस)।

साइकिल रेस

वाईरान में टूर डी फ्रांस साइकिल रेस में बेल्जियम के जैस्पर फिलीपैशन सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर उत्साहित होते हुए।

आस्ट्रेलिया दौरे से पहले बांग्लादेश को झटका, तेज गेंदबाज इबादत हुसैन बाहर

नई दिल्ली

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज इबादत हुसैन आस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इबादत अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण बांग्लादेश में ही रहेंगे और टीम के साथ आस्ट्रेलिया का दौरा नहीं करेंगे।

बांग्लादेश की टीम 13 अगस्त से डार्विन में शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में आस्ट्रेलिया का सामना करेगी। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 चक्र का हिस्सा है। फिलहाल बांग्लादेश डब्ल्यूटीसी अंकतालिका में चौथे स्थान पर है और इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा।

हालांकि इबादत की गैरमौजूदगी के बीच टीम को एक राहत भी मिली है। तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने आस्ट्रेलिया दौरे की बेहतर तैयारी के लिए श्रीलंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) से अपना नाम वापस ले लिया है।

तस्कीन ने कहा, मेरा मुख्य लक्ष्य आस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी करना है। हमने जिम्बाब्वे में लगातार छह मैच खेले हैं। अगर मैं एलपीएल भी खेलता और फिर सीधे आस्ट्रेलिया जाता तो टेस्ट मैच की तैयारी प्रभावित होती। इसलिए थोड़ा नुकसान उठाकर भी मैंने एलपीएल से हटने का फैसला किया। आस्ट्रेलिया जैसी टेस्ट सीरीज बार-बार नहीं आती। नाहिद राणा और लिटन दास की फिटनेस पर नजर बांग्लादेश के लिए एक और चिंता तेज गेंदबाज नाहिद राणा की फिटनेस है। उनके शरीर के साइड हिस्से में लगी चोट की स्कैन रिपोर्ट का टीम प्रबंधन को इंतजार है। वहीं अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास भी पिंडली (काफ) की चोट से उबर रहे हैं और टीम को उम्मीद है कि वह आस्ट्रेलिया के खिलाफ उपलब्ध रहेंगे। बांग्लादेश की टीम अगले महीने की शुरुआत में आस्ट्रेलिया पहुंचेगी, जहां 3 अगस्त से डार्विन में क्रिकेट आस्ट्रेलिया एकादश के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी। बल्लेबाजों पर जताया भरोसा बांग्लादेश के बल्लेबाजी कोच मोहम्मद अशरफुल ने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट में मिली बड़ी हार के बावजूद अपने बल्लेबाजों पर भरोसा जताया है। अशरफुल ने कहा, आस्ट्रेलिया में चुनौती कठिन होगी, लेकिन सकारात्मक बात यह है कि हम 10-12 दिन पहले वहां पहुंचेंगे और अभ्यास मैच खेलने का मौका मिलेगा। यदि सभी खिलाड़ी फिट रहे तो हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा, पिछले सात महीनों में हमारे बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। एक सीरीज या एक टेस्ट खराब होने का मतलब यह नहीं कि हम निराश हो जाएं। अलग-अलग परिस्थितियों में खेलने से खिलाड़ियों को अनुभव मिला है और हमें विश्वास है कि वे आस्ट्रेलिया में बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

चौथी हाकी इंडिया जूनियर महिला अकादमी चैंपियनशिप 24 जुलाई से, ग्वालियर करेगा मेजबानी

नई दिल्ली

भारतीय महिला हाकी की उभरती प्रतिभाओं को मंच देने वाला चौथा हाकी इंडिया जूनियर महिला अकादमी चैंपियनशिप 2026 (जोन ए एवं बी) शुक्रवार, 24 जुलाई से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू होगा। 11 दिनों तक चलने वाला यह टूर्नामेंट 3 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश की 12 प्रमुख जूनियर महिला हाकी अकादमियां खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी।

टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 12 टीमों को दो पूल में बांटा गया है। प्रत्येक पूल में छह-छह टीमें हैं और लीग चरण में सभी टीमें अपने-अपने पूल की अन्य टीमों से मुकाबला करेंगी। दोनों पूल से शीर्ष दो टीमें 2 अगस्त को होने वाले सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी, जबकि 3 अगस्त को तीसरे स्थान का मुकाबला और फाइनल खेला जाएगा।

पूल-ए में राजा करण हाकी अकादमी, खालसा हाकी अकादमी (अमृतसर), स्पोर्ट्स अथारिटी आफ गुजरात-हाकी अकादमी, हाकी फैमिली बढ़खालसा एनसीआर हाकी सोसायटी, तमिलनाडु हाकी अकादमी और प्रीतम सिवाच हाकी अकादमी, सोनीपत शामिल हैं।

वहीं पूल-बी में रितु रानी हाकी अकादमी, वडीपट्टी राजा हाकी अकादमी, भाई बेहलो हाकी अकादमी भगता, मुंबई स्कूल्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन, अड्यार हाकी अकादमी और मध्य प्रदेश हाकी अकादमी की टीमें खेलेंगी। टूर्नामेंट में लीग चरण के दौरान जीत पर तीन अंक, ड्रा पर एक अंक और हार पर कोई अंक नहीं मिलेगा। नाकआउट मुकाबलों में बराबरी की स्थिति होने पर विजेता का फैसला अंतरराष्ट्रीय हाकी महासंघ (एफआईएच) के नियमों के अनुसार शूटआउट से किया जाएगा। हाकी इंडिया के अध्यक्ष डा. दिलीप टिर्की ने कहा कि जूनियर महिला अकादमी चैंपियनशिप भारत में महिला हाकी के जमीनी ढांचे को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच बन चुकी है। इससे युवा खिलाड़ियों को देश की बेहतरीन अकादमियों के खिलाफ खेलने का अवसर मिलता है और भविष्य की राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों की पहचान करने में मदद मिलती है। हाकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा कि अकादमियां युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे टूर्नामेंट खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी माहौल और राष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्रदान करते हैं।

पहले दिन का कार्यक्रम

- सुबह 7:30 बजे: राजा करण हाकी अकादमी बनाम खालसा हाकी अकादमी (अमृतसर)
- सुबह 9:00 बजे: स्पोर्ट्स अथारिटी आफ गुजरात-हाकी अकादमी बनाम प्रीतम सिवाच हाकी अकादमी, सोनीपत
- सुबह 10:30 बजे: हाकी फैमिली बढ़खालसा एनसीआर हाकी सोसायटी बनाम तमिलनाडु हाकी अकादमी
- दोपहर 1:30 बजे: रितु रानी हाकी अकादमी बनाम वडीपट्टी राजा हाकी अकादमी
- दोपहर 3:00 बजे: मुंबई स्कूल्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनाम अड्यार हाकी अकादमी
- शाम 4:30 बजे: भाई बेहलो हाकी अकादमी भगता बनाम मध्य प्रदेश हाकी अकादमी।

यहां होती है चमगादडों की पूजा

वैसे तो आपने चमगादड़ों को देखा होगा, लेकिन बिहार के वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड के सरसई (रामपुर रत्नाकर) गांव में चमगादड़ों की न केवल पूजा होती है, बल्कि लोग मानते हैं कि चमगादड़ उनकी रक्षा भी करते हैं। इन चमगादड़ों को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यहां लोगों की मान्यता है कि चमगादड़ समृद्धि की प्रतीक देवी लक्ष्मी के समान हैं। सरसई गांव के एक बुजुर्ग गणेश सिंह का मानना है कि चमगादड़ों का जहां वास होता है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती। ये चमगादड़ यहां कब से हैं, इसकी सही जानकारी किसी को भी नहीं है। सरसई पंचायत के सरपंच और प्रदेश सरपंच संघ के अध्यक्ष आईएनएस को बताते हैं कि गांव के एक प्राचीन तालाब (सरोवर) के पास लगे पीपल, सेमर तथा बथुआ के पेड़ों पर ये चमगादड़ बसेरा बना चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस तालाब का निर्माण तिरहुत के राजा शिव सिंह ने वर्ष 1402 में करवाया था। करीब 50 एकड़ में फैले इस भूभाग में कई मंदिर भी स्थापित हैं।

बीमारियों का खतरा कम करता है अखरोट

अखरोट में जितनी कैलोरी होने की बात कही है, असल में, अखरोट में उससे 21 फीसदी कम कैलोरी होती हैं। अखरोट खाने के कई फायदों को भी बता सकते हैं जिनमें कैंसर, हृदय और कुछ अन्य बीमारियों के खतरे को कम करना शामिल है। उन्होंने कहा कि हमारे शोध से लोगों की कैलोरी संबंधित चिंताओं को कम करने में मदद मिल सकती है और वे अपनी रोज की खुराक में इसे शामिल कर सकते हैं।

प्राकृतिक गुणों से भरपूर अनानास

अनानास सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें कैल्शियम, फाइबर तथा विटामिन सी भरपूर मात्रा पाया जाता है और फैट बहुत कम होता है। गर्भावस्था में होने वाली मॉर्निंग सिकनेस की समस्या को कम करने में अनानास आपकी मदद कर सकता है। इस समस्या को कम करने के लिए खाली पेट अनानास को सेवन करना चाहिए। इसमें ब्रोमिलेन नामक तत्व सर्दी, खांसी, सूजन, गले में खराश और गठिया में फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में...

प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं

अनानास के सेवन से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इससे किसी भी तरह की एलर्जी का खतरा कम हो जाता है।

हड्डियां को बनाए मजबूत

इसमें मैग्नीशियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत और शरीर में एनर्जी को बनाएं रखने में मदद करता है।

आंखों के लिए फायदेमंद

हर रोज अनानास खाने से बढ़ती उम्र के साथ कम होती आंखों की रोशनी का खतरा कम हो जाता है।

दिल की बीमारियों से बचाव

यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। जिससे दिल की बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है।

कैंसर की रोकथाम

इसका एंटीऑक्सीडेंट आपको हृदय रोग, गठिया, विभिन्न तरह के कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं।

कैविटी से रखे दूर

यह मुंह के किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। जिससे दांतों में कैविटी की समस्या नहीं होती है।

उच्च रक्तचाप

अगर आप उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो अनानास आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता हैं। इसमें पोटेशियम की उच्च मात्रा और सोडियम की कम मात्रा रक्तचाप के स्तर को सामान्य बनाए रखने में मदद करती हैं।

ठंडी-ठंडी चिकित्सा पद्धति है क्रायोथेरेपी

क्रायोथेरेपी चिकित्सा की ऐसी पद्धति है जिसमें बर्फ के टुकड़े या ठंडे पानी के प्रयोग से दर्द का उपचार किया जाता है। इसका प्रयोग सबसे अधिक स्पोर्ट्स गतिविधियों के दौरान लगने वाली चोट के उपचार के लिए किया जाता है।

इसके अलावा क्रायोथेरेपी का प्रयोग प्रोस्टेट कैंसर और अनियंत्रित कोशिकाओं पर नियंत्रण पाने के लिए भी किया जाता है। क्रायोथेरेपी से शरीर के उस स्थान के बढ़े हुए तापमान को कम करता है, रक्त संचार की गति को बढ़ाता है, यह तंत्रिकाओं के वेग को भी कम कर देता है जिसके कारण दर्द को काबू में आ जाता है। इस लेख में विस्तार से जानिए इसका प्रयोग कैसे होता है और इसके विभिन्न तरीके क्या-क्या हैं।

कब प्रयोग करें

- चोट के कारण होने वाले वाले तेज दर्द को कम करने के लिए
- सूजन को कम करने के लिए
- शरीर के कोमल (tenderness) क्षेत्रों के उपचार के लिए
- मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन होने पर
- कुछ भड़काऊ स्थितियों (bursitis, tenosynovitis, tendinitis) में।
- अधिक दबाव के कारण होने वाले दर्द में
- डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने पर

कब प्रयोग न करें

- खुले घावों में इसका प्रयोग न करें
- उच्च रक्तचाप होने पर
- हृदय रोगों में
- त्वचा संक्रमण होने पर
- सनसनी होने पर
- शीत पित्ती (Cold Urticaria) में।

कोल्ड पैक्स

इस तरह का उपचार बर्फ के टुकड़े को तौलिये में या फिर आइस पैकेट में रखकर किया जाता है। यह शरीर के किसी हिस्से में होने वाले दर्द या फिर ऐंठन की समस्या को दूर करता है।

कोल्ड व्हर्लपूल मेथॉड

क्रायोथेरेपी से उपचार के इस तरीके में किसी टब में पानी भरकर उसे ठंडा कर दिया जाता है, फिर शरीर के जिस हिस्से का उपचार होना होता है उसे टब में डालकर शरीर के हिस्से को हिलाया जाता है। पैरों की समस्याओं के उपचार के लिए यह तरीका अधिक प्रयोग किया जाता है।

आइस इमर्सन

इस तरीके का प्रयोग एथलीटों या फिर स्पोर्ट्स गतिविधियों में लगे रहने वाले लोगों के लिए किया जाता है। इस तकनीक में पूरे टब में बर्फ के टुकड़े डाले जाते हैं उसके बाद मरीज को उस टब में घुसाया जाता है।

क्रायोथेरेपी यानी आइस थेरेपी दर्द की समस्या से निजात दिलाने वाला बहुत ही सामान्य और अच्छा तरीका है जिसका प्रयोग हर कोई आसानी से कर सकता है।

आइस मसाज

इस तरीके में बर्फ के टुकड़े को सीधे तौर पर चोट वाली जगह पर लगाया जाता है। दर्द को दूर करने के लिए यह बहुत ही सामान्य और असरदार तरीका है।

कीटनाशकों के प्रयोग से फैलता है नोरोवायरस

नोरोवायरस एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसका वायरस यदि शरीर में प्रवेश कर जाएं तो उल्टियां होती हैं। हालांकि यह किसी भी मौसम में हो सकता है। इस संक्रामक वायरस के कारण गंभीर उल्टी और दस्त की समस्या होती है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि ये वायरस कीटनाशकों की वजह से फैल सकता है, तो चलिये जानें कि

नोरोवायरस क्या है, इसके जोखिम क्या हैं और यह किस प्रकार फैल सकता है। यह वायरस बेहद तेजी से फैलता है और इससे संक्रमित होने पर फ्लू जैसे लक्षण नजर आते हैं जिनमें पेट दर्द तथा उल्टी भी शामिल होते हैं।

कैसे फैलता है नोरोवायरस

किसानों द्वारा कीटनाशकों के मिश्रण को पतला करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला गंदा पानी नोरोवायरस फैला सकता है। दरअसल किसान कीटनाशकों के मिश्रण को पतला करने के लिए कुओं, सिंचाई होदियों, नदियों, और झीलों जैसे स्रोतों से पानी लेते हैं। और इन सभी पानी के स्रोतों में नोरोवायरस भरे होते हैं।

भोजन के माध्यम से भी फैलता है नोरोवायरस

नोरोवायरस अपके भोजन के माध्यम से भी फैल सकता है। नोरोवायरस रेस्तरां में बनाए गए और डिब्बे बंद खाद्य पदार्थों में हो सकता है। क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में कई सारी अलग-अलग सामग्री होती हैं, नोरोवायरस किस खाद्य पदार्थ से शरीर में गया है, पता लगाना मुश्किल होता है। कई प्रकार के तैयार खाने व खाद्य पदार्थों जैसे, सलाद, सैंडविच, बर्फ, कुकीज, और फल भी इसके लिए जोखिम कारक बन सकते हैं। यदि खाने के बाद उल्टी या दस्त की समस्या हो तो यह नोरोवायरस संक्रमण के कारण भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इस संक्रमण के लक्षण तुरंत दिखाई दें, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपको इसके लक्षणों का अनुभव हो।

ध्यान रहे कि भोजन को गर्म करना इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। नोरोवायरस 140 डिग्री फेरनहाइट तक ताप पर जीवित रह सकते हैं। यह वायरस ठंड से जमाने पर भी जीवित रह सकता है।

टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी पानी की बोतल!

एक पानी की बोतल को बार-बार इस्तेमाल न करें। ये आपकी टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी हो सकती है और कई तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वैज्ञानिकों ने हालिया शोध में पाया है कि प्लास्टिक की पानी की बोतलों का इस्तेमाल लंबे समय तक बार बार करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। शोधकर्ताओं के अनुसार बोतल पर जमा होने वाले बैक्टीरिया में से करीब साठ प्रतिशत कीटाणु ऐसे होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। इसके चलते डायरिया, फूड पाइजनिंग, नौजिया और उल्टी जैसी समस्याएं आमतौर पर होने का खतरा रहता है। शोध में इस्तेमाल की गई ऐसी बोतलों का लैब में परीक्षण किया गया। चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पाया गया कि उसके सेंटीमीटर के एरिया में करीब नब्बे हजार बैक्टीरिया थे, जो एक टॉयलेट सीट पर इतने क्षेत्र में मौजूद कीटाणुओं से कहीं ज्यादा हैं। बोतल के मुंह पर सबसे ज्यादा कीटाणु पाए गए। वहीं स्ट्रॉ के ऊपरी हिस्से पर भी उतने ही बैक्टीरिया मिले। बोतल धोने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। धोने के बावजूद बैक्टीरिया थोड़ी देर के लिए ही खत्म होते हैं, फिर पनप जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस पानी की बोतल का आप बार-बार पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वह आपके लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है।

इन नुस्खों से मिलेगी दो मुंहे बालों से मुक्ति

वैसे तो हर महिला को लंबे, काले, घने और रेशमी बालों चाहिए, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल और प्रदूषण के चलते आजकल बाल बहुत डेमेज होते हैं पार्लर में न करें पैसा बर्बाद वैसे तो हर महिला को लंबे, काले, घने और रेशमी बालों चाहिए, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल और प्रदूषण के चलते आजकल बाल बहुत डेमेज होते हैं। बालों का दुमुहां होना आम समस्या है। महिलाएं अक्सर पार्लर में पैसा खर्च करके अपने बाल कटवाती हैं। लेकिन कुछ टिप्स अपनाकर इन दोमुहें बालों से मुक्ति पा सकते हैं।

पपीता और दही: पपीते और दही का घरेलु पैक लगाएं। 150 ग्राम पपीता और आधा कप दही मिलाएं और बालों में लगाएं। फिर ठंडे पानी से धो लें।

अंडे का मास्क: अंडे का पीला भाग, तीन टेबल स्पून ऑलिव ऑयल और एक टेबल स्पून शहद मिलाएं। पैक को बालों में 20 से 30 मिनट तक लगा रहने दें। फिर शैंपू से धो लें।

हॉट ऑयल ट्रीटमेंट: दो मुहें बालों के लिए हॉट ऑयल ट्रीटमेंट भी काफी अच्छा है। यह काफी असरदार माना जाता है।

शहद के साथ दही: यह एक नेचुरल कंडीशनर है। इसके और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए दही भी मिला दें। एक कप दही में एक टेबल स्पून शहद मिलाएं और उसे जड़ों पर लगाते हुए सिरों तक लगाएं। उसके बाद इस पैक को धो लें।

सुख-सुविधाओं के जाल में फंसते जा रहे हैं लोग

सफलता की होड़ में उधड़ते मानवीय रिश्ते

पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव ने हमारे देश में भौतिकवाद को प्रोत्साहन दिया है और अब तो पढ़े लिखे हों या नहीं सभी सुख-सुविधाओं के जाल में फंसते जा रहे हैं। भारतीय अध्यात्म ज्ञान के बारे में जानते सभी हैं पर उसे धारण करना लोगों को अब पिछड़ापन दिखाई देता है। नतीजा यह है कि समाज में आपसी रिश्ते एक औपचारिकता बनकर रह गए हैं।

सिर्फ सांसारिक शिक्षा काफी नहीं

अक्सर अनेक लोग शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं अथवा उनकी देखभाल नहीं करते। इसके दो कारण होते हैं एक तो यह कि नए सामाजिक परिवेश से तालमेल न बिठा पाने के कारण लोग अपने माता-पिता को त्याग देते हैं या फिर वह व्यवसाय के सिलसिले में उनसे दूर हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियों का विश्लेषण करने पर अनुभव होगा कि आधुनिक युग के समस्त माता-पिता अपने बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि वह इस मायावी दुनिया में उच्च से उच्च पद प्राप्त कर, अधिक से अधिक धनार्जन करें और भरपूर मान प्रतिष्ठा की दुनिया में चमककर उनका व अपना नाम रोशन करें। लोग बच्चों की कामयाबी के सपने देखते हैं और केवल सांसारिक शिक्षा तक ही अपने बच्चों को सीमित रखते हैं। किसी तरह अपना पेट पालो यही सिखाते हुए वह ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे कि वह दुनियां का कोई विशेष ज्ञान दे रहे हैं। यह तो एक सामान्य चतुराई है, जिसे सब जानते हैं।

सभी सुविधाओं के बाद भी अशांत रहता है मन

यह उन माता-पिता का भ्रम है कि शिक्षा तो सभी स्वतः ही प्राप्त करते हैं पर जिन बच्चों को उनके माता-पिता इसके साथ ही अध्यात्म ज्ञान, ईश्वर भक्ति और परोपकार करना सिखाते हैं वह अधिक योग्य निकलते हैं। जब तक आदमी के मन में अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह न तो स्वयं कभी प्रसन्न रह पाता है और न ही दूसरों को प्रसन्न करता है। आज समस्त सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी बहुत सभी लोगों का मन अशांत रहता है, क्योंकि मानव को परमात्मा के ज्ञान का प्रत्यक्ष बोधकर शांति, सत्य, अहिंसा एवं निःस्वार्थ प्रेम का वातावरण स्थापित करने का समय नहीं है। वह तो पैसे कमाने और सफलता की दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहते हैं। मनुष्य जीवन में भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा मिलती है पर उसका उपयोग नहीं कर हम उसे ऐसे ही नष्ट कर डालते हैं। ऐसे में वह ज्ञानी धन्य है जो दाल-रोटी खाकर पेट भरते हुए भगवान भजन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय निकालते हैं।

रेसिपी

ब्रेड कटलेट

सामग्री

4 ब्रैड स्लाइस,1 आलू(उबला हुआ), आधा कप मटर(उबले हुए),1 गाजर(कद्दूकस की हुई),1 कप गोभी(कद्दूकस की हुई), 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, 1 प्याज (बारीक कटा),1 हरी मिर्च(कटी हुई),आधा चम्मच अदरक(कसा हुआ),गरम मसाला,1 छोटा चम्मच नींबू का रस, तेल, नमक स्वादानुसार,पानी,3-4 पनीर(टुकडों में कटा)

विधि

एक कड़ाही में तेल डालकर इसमें प्याज,अदरक और हरी मिर्च डालकर इसे हल्का गुलाबी होने तक भूनें। अब इसमें गाजर,मटर और गोभी डालें। अब इसमें गर्म मसाला डालकर मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए भूनें और गैस बंद कर दें। ब्रेड को पानी में भिगोकर निचोड लें और इसे पकी हुई सब्जियों में डाल लें और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें आलू,ब्रेड क्रम्स,नींबू का रस और नमक डाल कर मिलाएं। इस मिश्रण को टिकी का आकार दें और एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स डालकर कटलेट को इसमें लपेट कर एक अलग प्लेट में रख लें। एक नॉन स्टिक पैन में तेल डालकर इसमें कटलेट को फ्राई करें। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तले। इन सबको प्लेट में निकाल कर ऊपर से पनीर के साथ गार्निश करके सॉस के साथ सर्व करें।

पास्ता बटर मसाला

सामग्री

1 कप पास्ता, 1 बड़ा चम्मच लहसुन(पिसा हुआ), आधा चम्मच अदरक(पिसा हुआ),1 टमाटर(कटा हुआ),2 प्याज(कटे हुए),1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाऊडर,1 छोटा चम्मच जीरा पाऊडर, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी,2 कप दूध, 2 बड़ा चम्मच तेल,1 छोटा चम्मच हरा धनिया(कटा हुआ), स्वादानुसार नमक

विधि

सबसे पहले एक पैन में थोडा सा नमक मिलाकर इसमें 2-3 बूंद तेल,पास्ता और पानी मिलाकर उबालें। जब पास्ता पक जाए तो इसे पानी से निकाल कर रख दें। अब एक पैन में तेल डालकर इसमें प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन डालकर भूनें और थोडा ठंडा होने पर मिक्सर में पीसकर पेस्ट बना लें। इसके बाद कड़ाही में तेल गर्म करके इलमें पीसा हुआ पेस्ट और नमक डालकर तेल छोड़ने तक भूनें और इसमें लाल मिर्च,गरम मसाला और जीरा डालकर गाढ़ा हाने तक पकाएं। इसके बाद इसमें दूध डाल दें। जब दूध और मसाले अच्छी तरह उबलकर सॉस बन जाए तो इसमें कसूरी मेथी और उबला हुआ पास्ता डालकर मिलाएं। गैस बंद करके गर्मागर्म पास्ते पर हरा धनिया डालकर सर्व करें।

प्राणघातक हो सकती है कैल्शियम की कमी

कई रोगों पर भी पड़ता है असर...

यदि व्यक्ति के भोजन में लगातार कैल्शियम या विटामिन 'डी' की कमी चलती रहे तो उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। नए शोधों के अनुसार कैल्शियम की कमी का कई रोगों पर भी प्रभाव पड़ता है।

शरीर होता है कमजोर

हमारे भोजन से हड्डियों को कैल्शियम मिलने और हड्डियों से शरीर को कैल्शियम मिलने की प्रक्रिया के लिए विटामिन 'डी' की उपस्थिति अनिवार्य है। विशेषज्ञों के अनुसार हर वयस्क को न्यूनतम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की दैनिक आपूर्ति होनी आवश्यक है। यदि भोजन से इतना कैल्शियम नहीं मिल पाता तो हमारे शरीर को पैराथायराइड हार्मोन विटामिन 'डी' के सहयोग से हड्डियों से रक्त का कैल्शियम स्थानांतरित कर देता है। जिससे हमारे शरीर में कमजोरी की शिकायत आने लगती है।

अपने आहार को करें संयोजित...

हम अपने आहार को इस प्रकार संयोजित करें कि हमें लगभग 1200 मिग्रा कैल्शियम प्रतिदिन मिलता रहे। 240 मिली गाय के दूध में 288 मिग्रा कैल्शियम होता है, जबकि 200 ग्राम दही में 268 मिग्रा कैल्शियम होता है। 100 ग्राम सूखे नारियल में 400 मिग्रा कैल्शियम होता है, जबकि 100 ग्राम खजूर में 120 मिग्रा कैल्शियम होता है। गुड़, पनीर, सोयाबीन, फूलगोभी व मछलियों में भी कैल्शियम पाया जाता है।

पेट के कैंसर से करता है बचाव...

हमारे शरीर में बहुत से सेल बनते रहते हैं और समाप्त होते रहते हैं। पेट के अंदर ऐसे सेल प्रायः 3 से 10 दिन में बदल जाते हैं पर कभी-कभी ये सेल तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं, जिससे पेट के कैंसर की संभावना हो सकती है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित एक लेख के अनुसार जिन लोगों में पेट के कैंसर की संभावना थी, उन्हें 1500 मिग्रा कैल्शियम प्रतिदिन दिए जाने पर सेलों में बढ़ोत्तरी ठीक हो गई।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**